शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 325 | गुवाहाटी | बुधवार, 1 जुलाई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

देशभर में कल से लागू होगा वीबी-जी राम-जी अधिनियम पेज 2
कामरूप मेट्रो प्रशासन ने दी भूस्खलन संवेदनशील पहाड़ों के निवासियों ... पेज 3
राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आज आस्था की दुहाई दे रह पेज 5
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में विराट की वापसी के बाद ईशान नंबर 4 पर.. पेज 7

असम में एकीकृत बाढ़ प्रबंधन से दीर्घकालिक समाधान की दिशा में बढ़ रही सरकार

गुवाहाटी (हि.स./नि.सं.)। असम सरकार ने कहा है कि राज्य में बाढ़ की समस्या केवल असम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे हिमालयी नदी तंत्र से जुड़ा एक व्यापक मुद्दा है। असम प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता मीता नाथ बोरा ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि पिछले कई दशकों तक बाढ़ प्रबंधन मुख्य रूप से तटबंध निर्माण, सीमित ड्रेजिंग, राहत एवं पुनर्वास, कटाव नियंत्रण तथा मुआवजा वितरण तक ही सीमित रहा, जबकि अब सरकार दीर्घकालिक और वैज्ञानिक समाधान की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बती पठार और युवा हिमालयी क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिसके कारण इसमें भारी मात्रा में गाद जमा होती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, भूटान और नगालैंड से आने वाली 50 से अधिक नदियां मानसून के दौरान बड़ी मात्रा में पानी लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती हैं। लगातार नदी का मार्ग बदलना और तीव्र कटाव भी असम में बाढ़ की प्रमुख वजह है। मीता नाथ बोरा ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, भूटान और तिब्बत में होने वाली भारी वर्षा का सीधा असर असम में बाढ़ की स्थिति पर पड़ता है। वहीं, अनियोजित शहरीकरण, आर्द्रभूमियों में कमी और जल निकासी व्यवस्था के बाधित होने से गुवाहाटी सहित कई शहरों में शहरी बाढ़ की समस्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ऊपरी क्षेत्रों में बने अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएं -शेष पृष्ठ दो पर

अरुणाचल में बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने की बैठक

इटानगर। अरुणाचल प्रदेश में जारी बाढ़ की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक (सेवानिवृत्त) से मुलाकात कर राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ से उत्पन्न हालात और राहत-बचाव कार्यों की जानकारी दी। बैठक में राज्य के विकास कार्यक्रमों और सामाजिक-आर्थिक प्रगति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, राहत सामग्री पहुंचाने और आवश्यक सेवाएं बहाल करने के लिए विभिन्न विभाग लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया। राज्यपाल ने बाढ़ से जनजीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे पर पड़े प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौती से निपटने के लिए पूरे राज्य को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने सभी सरकारी विभागों, जिला प्रशासन, सामुदायिक संगठनों और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया, ताकि राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकें। राज्यपाल ने राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में जुटे राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों के प्रयासों की सराहना की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने हाल में राजभवन में हुई -शेष पृष्ठ दो पर

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को बनाया जाएगा समन्वित ग्रामीण सेवा केंद्र : सीएम

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि समृद्ध किसान ही समृद्ध असम की मजबूत नींव हैं। किसानों को सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर सरल और सुगम तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसीएस) को चरणबद्ध तरीके से समन्वित ग्रामीण सेवा केंद्रों (इंटीग्रेटेड रूरल सर्विस सेंटर) में परिवर्तित कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच *एक्स* पर जारी अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इस नई पहल के माध्यम से पीएसीएस केवल सहकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ग्रामीण नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समन्वित ग्रामीण सेवा केंद्रों के -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने कुकी-जो समुदाय का मार्च रोका, छोड़े आंसू गैस के गोले

इंफाल। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (एनएच-2) पर आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर कुकी-जो समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जब गमगीफाई स्थित बफर जोन की ओर मार्च करते हुए आगे बढ़ने लगे तो सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक गतिरोध बना रहा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और धुआं बम का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन का आयोजन कुकी-जो समुदाय के संगठन कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने किया था। प्रदर्शनकारी तालौलोंग क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां से बफर जोन की ओर मार्च शुरू -शेष पृष्ठ दो पर

door graph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है।

\- आचार्य चाणक्य

गोगोई ने राज्य सरकार पर सीमावर्ती गांवों की देखभाल में विफल रहने का आरोप लगाया

जोरहाट। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मंगलवार को हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार पर असम के क्षेत्रीय हितों और असम-नगालैंड सीमा पर रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले अतिक्रमण और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण सीमावर्ती समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और जोरहाट जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ, गोगोई ने नागजान गांव सहित मारियानी का दौरा किया, जहां के निवासियों ने हाल ही में आरोप लगाया था कि नगालैंड प्रशासन की आपत्तियों के -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने की प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन है : ओराम

गुवाहाटी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने मंगलवार को कहा कि असम में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा चाहने वाले छह समुदायों को अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत शामिल करने या बाहर करने की प्रक्रिया व्यापक है और इसमें कई संवैधानिक प्राधिकरण शामिल हैं। गुवाहाटी के कोइनाधारा में असम के जनजातीय मामलों (मैदानी) विभाग के कामकाज की समीक्षा करने के बाद असम के शिक्षा एवं मैदानी जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण मंत्री रानोज पेगू और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए ओराम ने कहा कि केंद्र निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत समावेशन और अपवर्जन का मुद्दा एक लंबी और सुस्पष्ट प्रक्रिया से जुड़ा है। इसमें राज्य सरकार की सिफारिशें, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जांच, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा परीक्षण और अंत में केंद्र सरकार द्वारा विचार-विमर्श शामिल है। चूंकि इसमें कई संस्थाएं शामिल हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से समय लगता है। केंद्र सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले समुदायों -शेष पृष्ठ दो पर

जनरल धीरज सेठ बने भारत के 31वें आर्मी चीफ

नई दिल्ली। जनरल धीरज कुमार सेठ ने मंगलवार 30 जून से भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख (सीओएएस) की कमान संभाल ली है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है, जो मंगलवार को सेवा से रिटायर हुए। जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला के पूर्व छात्र रहे हैं। दिसंबर 1986 में उन्हें आर्मर्ड कोर में कमीशन मिला था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, लगभग चार दशकों के अपने शानदार सैन्य करियर के दौरान, उन्हें ऑपरेशनल, रणनीतिक, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में अनुभव मिला है। उन्होंने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और लंबे समय के बदलाव में अहम योगदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने रेगिस्तानी इलाके में एक बख्तरबंद रेजिमेंट और जम्मू-कश्मीर -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

कर्नाटक में अब बिना इजाजत मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे पुलिसकर्मी

बेंगलुरु। कर्नाटक पुलिस विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन को लेकर एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है। अब राज्य का कोई भी आम पुलिसकर्मी अपनी मर्जी से न तो मीडिया से बात कर पाएगा और न ही सोशल मीडिया पर पुलिस से जुड़ी कोई जानकारी शेयर कर सकेगा। इस संबंध में -शेष पृष्ठ दो पर

एफआईआर से चार्जशीट तक हर कदम ऑनलाइन...

2027 से हर केस की होगी डिजिटली जांच, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। तीन नए कानून देश में लागू होने के दो साल पूरे होने पर गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन्वेस्टिगेशन पर बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2027 से देशभर में डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था पुलिस द्वारा की जाएगी। देश भर के संबंधित पुलिस थानों में इसका इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड रखा जाएगा। केस में ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज होने से चार्जशीट दाखिल होने तक रहेगी। दरअसल, देश में 1 जुलाई 2024 को तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2026 को इसने दो साल पूरे कर लिए हैं। इन कानूनों ने अंग्रेजों के जमाने के -शेष पृष्ठ दो पर

सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : गडकरी

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें होती हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। गडकरी ने यहां मंगलवार को उबर के एक कार्यक्रम में कहा अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल -शेष पृष्ठ दो पर

चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 23 विपक्षी दल

सीजेआई सूर्यकांत को लिखा संयुक्त पत्र

नई दिल्ली। देशभर में जहां एक ओर बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार को लेकर विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया चला रही है। वहीं दूसरी इसी मामले में जारी सियासी गर्माहट को और तेज कर दिया है। कारण है कि देशभर की 23 राजनीतिक पार्टी एक निर्दलीय सांसद ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत को एक साझा पत्र भेजा है। इस पत्र में चुनाव आयोग की भूमिका और -शेष पृष्ठ दो पर

पाकिस्तान के रावलपिंडी में जेल वैन से 14 कैदी भागे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेलों में गिनी जाने वाली अदियाला जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। यही वह जेल है, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले कई महीनों से बंद हैं। लेकिन, इस बार चर्चा इमरान खान की नहीं, बल्कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों की हो रही है। खबर है कि इसी हाई-सिक्योरिटी जेल से 14 कैदी फरार हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने फरार कैदियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अदियाला सेंट्रल जेल को रावलपिंडी जिला जेल भी कहते हैं, इसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, -शेष पृष्ठ दो पर

मिडिल ईस्ट युद्ध के असर

45 मिलियन लोगों पर आ सकता है गरीबी का संकट : यूएन रिपोर्ट

संरा। ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच अप्रैल में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट ने अंदेशा जताया था कि यूएस-इरान वार से वेस्ट एशिया में बढ़ती जियो-पॉलिटिकल टेंशन से ग्लोबल एनर्जी मार्केट के साथ ही कमोडिटी बाजारों में भयानक असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म होने के बावजूद यह संकट खत्म होते नहीं दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक विकास नेटवर्क यूएनडीपी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध खत्म होने के बावजूद, आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक तौर पर इसका असर बना रह सकता है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग गरीबी के शिकार गो सकते हैं। काम में निकालते थे कमी, 1000 रुपए लिए, मारपीट कर घर से निकाला... आईपीएल क्रिकेटर शशांक और उनके रिटायर्ड आईपीएस पिता पर एफआईआर -शेष पृष्ठ दो पर

बांग्लादेश में मंदिर के पुजारी का अपहरण

ढाका। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस कार्यकाल में हिंदूओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा का दौर प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार के दौर में भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कानून की पढ़ाई करने वाले हिंदू छात्र, जो मंदिर के पुजारी का काम भी करते हैं, उनका अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया, उन्हें बंधक बनाया और उनके साथ मारपीट की। अपहरणकर्ताओं ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उनके कपड़े उतरवाए और फिरौती की रकम का इंतजाम करने के लिए परिवार और दोस्तों को फोन करने पर मजबूर किया। पीड़ित की पहचान जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में कानून के छात्र 25 वर्षीय सुभाष देउरी के तौर पर हुई है। सोमवार देर रात अज्ञात लोगों के एक ग्रुप ने उन्हें निशाना बनाया और पैसे की मांग की। -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED
For all kinds of classified advertisements please contact
97070-14771
94350-14771

देशभर में कल से लागू होगा वीबी-जी राम-जी अधिनियम

नई दिल्ली (हि.स.)। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम-जी) अधिनियम बुधवार से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। अधिनियम के देशव्यापी क्रियान्वयन से पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी वक्तव्य में कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रोजगार की गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका और मजबूत होगी, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि देशभर में अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इससे अधिनियम लागू होने के पहले दिन से रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को बिना किसी बाधा के जारी रखने में मदद मिलेगी। सरकार ने नए ढांचे में निर्बाध बदलाव सुनिश्चित किया है। पहले से चल रहे सभी कार्य जारी रहेंगे। जिन श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे, ताकि रोजगार और मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट न आए। इस अधिनियम में ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अधिक मजबूत किया गया है। इसके तहत टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल संरक्षण, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, विभिन्न सरकारी योजनाओं का बेहतर समन्वय तथा प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शी व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। वीबी-जी राम-जी अधिनियम का लागू होना ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे गांवों में आजीविका के अवसर बढ़ेंगे, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं सशक्त ग्रामीण भारत के निर्माण को नई गति मिलेगी। विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के ओबुलावरिपल्ले मंडल के मुक्कावरिपल्ली गांव में आयोजित किया जाएगा।

स्वस्थ भारत से ही विकसित भारत का निर्माण संभव : नड्डा

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को कहा कि स्वस्थ भारत से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। देश में *निवारक स्वास्थ्य देखभाल* को अब ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ताकि लोग गंभीर बीमारियों से पहले ही सुरक्षित रह सकें। स्वस्थ भारत ही विकसित भारत की नींव है और इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। मंगलवार को जे पी नड्डा इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस) के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए *हार्डवेयर* और *सॉफ्टवेयर* दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया है। उनके अनुसार, हार्डवेयर का मतलब है अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, जबकि सॉफ्टवेयर का अर्थ है बेहतर नीतियां, प्रशिक्षण और ऐसा शैक्षणिक माहौल जो डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को आगे बढ़ने में मदद करे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 818 हो गई है। इसी तरह एमबीबीएस सीटें लगभग 50 हजार से बढ़कर 1.20 लाख से अधिक हो गई हैं, जबकि पीजी सीटें 30 हजार से बढ़कर 80 हजार से अधिक पहुंच चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में और 75 हजार नई मेडिकल सीटें जोड़ने का है, जिससे देश में डॉक्टरों की उपलब्धता और बेहतर हो सके। अपने संबोधन में मंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत में 23 एम्स काम कर रहे हैं, जिनमें से कई हाल के वर्षों में शुरू किए गए हैं। यह विस्तार देश में सुपर-स्पेशियलिटी इलाज और मेडिकल शिक्षा को नई दिशा दे रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हुए उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की भूमिका को अहम बताया। देशभर में 1.85 लाख से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं, जो लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में लोगों की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की जा रही है। समय पर जांच से कई मरीजों में बीमारी का शुरुआती चरण में ही पता लग रहा है, जिससे इलाज आसान हो रहा है।

वीबी-जी राम-जी के कार्यों का समय प्रातः नौ बजे से सायं पांच बजे तक रहेगा

जयपुर (हिंस)। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत वीबी-जी रामजी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कार्य का समय परिवर्तित किया गया है। अब कार्यों का संचालन प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे तक विश्राम काल रहेगा। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् प्रतिभा वर्मा ने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह निर्धारित समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है, तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में दर्ज कराने तथा समूह के मुखिया के हस्ताक्षर करवाने के उपरांत कार्यस्थल सकेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित मेट निर्धारित समय तक कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा। साथ ही स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था के दौरान श्रमिकों को निर्धारित टास्क में किसी प्रकार की अतिरिक्त कमी नहीं की गई है।

हिसार में अध्यापकों ने सांकेतिक भूख हड़ताल से किया आंदोलन का आगाज

हिसार (हिंस)। अध्यापकों की विभिन्न मांगों और समस्याओं के हल के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त आह्वान पर मंगलवार को जिला प्रधान प्रमोद जांगड़ा की अध्यक्षता में एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की गई। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव विनोद प्रभाकर ने किया। भूख हड़ताल की शुरुआत पूर्व अध्यापक नेता सुरेंद्र सैनी, जयवीर सिंह, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान अशोक सैनी, किसान सभा के जिला प्रधान कपूर सिंह बगला, शमशेर सिंह नम्बरदार, सर्व कर्मचारी संघ हिसार ब्लॉक के प्रधान राजेश बागड़ी, ब्लॉक सचिव जयकुमार सिवाच, हेमसा के राज्य महासचिव हितेंद्र सिहाग, अध्यापक संघ की राज्य उपप्रधान अलका तथा जनवादी महिला समिति की जिला सचिव बबली लांबा ने पदाधिकारियों को मालाएं पहनाकर की। एक दिवसीय भूख हड़ताल पर राजेश मेहरा, अशोक यादव, संदीप मिरका, नरेंद्र लोरा, विजय कुमार, पवन कुमार, राजेंद्र दूहन, सुरेश कुमार, कृष्ण भर्री, राजेश जागलान, सुमन देवी और रामनाथ बैठे। इस अवसर पर वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और हरियाणा सरकार की नीतियों से सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 से पहले नियुक्त अध्यापकों पर भी सेवानिवृत्ति एवं सेवा संबंधी विभिन्न शर्तें लागू की जा रही हैं।

अरुणाचल में चीनी सेना के कैंप का दावा सरासर झूठ : सेना

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने सोमवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया जिनमें दावा किया गया था कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में कब्जा कर मिलिट्री कैंप स्थापित कर लिए हैं। सेना ने इन खबरों को गलत और बेबुनियाद बताया है। भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि चीनी पीएलए ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप बनाए हैं। ये रिपोर्ट्स गलत और पूरी तरह से बेबुनियाद हैं इनका कोई आधार नहीं है। सेना ने साफ किया कि सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। दरअसल हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसपैठ कर वहां अपने नए कैंप स्थापित कर लिए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश के सामुदायिक संगठन नाह वेलफेयर सोसायटी (एनडब्ल्यूएस) ने स्थानीय प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था। इसमें कहा गया था चीनी सेना ने पिछले कई सालों के दौरान राज्य के बॉर्डर से सटे दूरस्थ इलाकों में धीरे-धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ा ली है। ज्ञापन के मुताबिक, एनडब्ल्यूएस ने दावा किया कि पिछले छह सालों में चीन ने नाह आदिवासी समुदाय की पारंपरिक चरागाह, शिकार और कृषि भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। एनडब्ल्यूएस अध्यक्ष केरु चाडेर ने आरोप लगाया कि जिन इलाकों में स्थानीय लोग पहले आजादी से जाते थे, अब वहां चीनी सेना का नियंत्रण है। केरु चाडेर ने डिप्टी कमिश्नर को दिए ज्ञापन में कहा कि हमारी पैतृक जमीनें, जो कुछ साल पहले तक हमारे शिकार के इलाके थे जहां हम आजादी से घूमते थे और वन उत्पाद इकट्ठा करते थे और हमारे मवेशियों के चरने की जगहें अब चीनी पीएलए के कब्जे में हैं। संगठन ने आगे आरोप लगाया कि चीन ने सीमा क्षेत्र में सड़क, पुल और सैन्य शिविर बनाकर लगातार अपना दायरा बढ़ाया है। वहीं भारतीय सेना ने कहा कि हमने ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखी है जिसमें दावा किया गया है कि चीनी आर्मी- पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण कर कैंप बना लिए हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स गलत और आधारहीन है। सेना ने स्पष्ट किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं हुई है।

पृष्ठ एक का शेष

असम में एकीकृत बाढ़ ...

बिजली उत्पादन के उद्देश्य से विकसित की गईं, जिनमें बाढ़ नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने बताया कि असम का लगभग 40 फीसदी भौगोलिक क्षेत्र, यानी करीब 31.05 लाख हेक्टेयर भूमि, हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। इसे देखते हुए पिछले एक दशक में राज्य सरकार ने बाढ़ एवं कटाव प्रबंधन को मजबूत करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। पिछले पांच वर्षों में लगभग 700.3 किलोमीटर नए तटबंध बनाए गए, 540.2 किलोमीटर पुराने तटबंधों को मजबूत किया गया, 320.3 किलोमीटर संवेदनशील नदी तटों पर 280 कटाव रोधी परियोजनाएं लागू की गईं तथा जल निकासी सुधारने के लिए 43 स्लूइस गेट बनाए गए। उन्होंने दावा किया कि हाल की बाढ़ के दौरान 1,240.5 किलोमीटर तटबंधों में से केवल एक तटबंध ही क्षतिग्रस्त हुआ। बोरा ने कहा कि राज्य सरकार ने दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन के लिए असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर इरोजन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट तथा नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से वैज्ञानिक आंकड़ों, आधुनिक तकनीक और जलवायु अनुकूल रणनीतियों के आधार पर समग्र नदी बेसिन प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाढ़ की चुनौती बनी हुई है, लेकिन नई पहलें असम में टिकाऊ और प्रभावी बाढ़ प्रबंधन की मजबूत नींव रख रही हैं।

अरुणाचल में बाढ़ ...

विभिन्न समीक्षा बैठकों का भी उल्लेख किया। उन्होंने राज्य के वित्तीय लेखा परीक्षण, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, इटानगर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियानों तथा नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हाल में हुई अव्यवस्था की घटना पर भी चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास एवं जनकल्याण कार्यक्रमों की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार, आधारभूत ढांचे के विकास और जनसेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई कि मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी निर्धारित समय पर आगे बढ़ाया जाएगा।

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी ...

माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को तकनीकी सहायता, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा विभिन्न जनकल्याणकारी सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीणों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और सरकारी सेवाओं की पहुंच अधिक तेज, सरल एवं पारदर्शी बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। आधुनिक तकनीक के उपयोग तथा डिजिटल सेवाओं के विस्तार से कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी और किसानों को समय पर आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होंगी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। डॉ. शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि पीएसीएस को समन्वित ग्रामीण सेवा केंद्रों के रूप में विकसित करने की यह पहल गांव-गांव तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करेगी। साथ ही किसानों को अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मणिपुर में सुरक्षा बलों ...

किया। संगठन का आरोप है कि कांगलाटोंगबी क्षेत्र के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही लंबे समय से प्रभावित है, जिससे कुकी-जो बहुल इलाकों में खाद्यान्न, दवाइयों और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित हो रही है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बफर जोन पार कर आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर बैठ गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। बाद में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। संगठन ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित रहने से संबंधित क्षेत्रों में सामान की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा एजेंसियों से निष्पक्ष तरीके से काम करने और राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही जल्द बहाल करने की मांग की। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक प्रदर्शनकारियों के आरोपों पर राज्य सरकार या सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग-2 राज्य की सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनों में से एक बना हुआ है। इसी मार्ग से राज्य के विभिन्न हिस्सों तक खाद्यान्न, दवाइयां, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होती है। ऐसे में इस राजमार्ग पर किसी भी तरह का व्यवधान जनजीवन और आपूर्ति व्यवस्था पर सीधा असर डालता है। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

गोगोई ने राज्य सरकार ...

बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत काम रोक दिया गया था। अपनी यात्रा के दौरान, गोगोई ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की, जिन्होंने कथित भूमि अतिक्रमण, विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध और अंतर-राज्यीय सीमा पर बार-बार होने वाले विवादों को लेकर चिंता व्यक्त की। खबरों के मुताबिक, उन्होंने नगालैंड पक्ष के अधिकारियों से भी मुलाकात की और उनसे असम द्वारा दावा की गई भूमि पर कथित अतिक्रमण, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में पूछताछ की। प्रेस को संबोधित करते हुए, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के प्रमुख ने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में असम-नगालैंड सीमा पर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, विशेष रूप से मारियानी, उरियामघाट और मेरापानी में, जहां स्थानीय निवासियों के अनुसार, असमिया किसानों द्वारा पारंपरिक रूप से खेती की जाने वाली कृषि भूमि पर धीरे-धीरे अतिक्रमण हो गया है। सीमा के असम की ओर रहने वाले लोगों ने शिकायत की है कि नगा समूह धीरे-धीरे मान्यता प्राप्त सीमा से आगे बढ़कर उन क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहे हैं जहां असम के किसान वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। पिछले 10-11 वर्षों में मारियानी में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यह असम की संवैधानिक सीमा है और इसकी रक्षा करना सरकार का दायित्व है, गोगोई ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित असम-नगालैंड सीमा विवाद का जिक्र करते हुए, गोगोई ने सवाल उठाया कि विवादित क्षेत्रों में स्थायी निर्माण गतिविधियों को कथित तौर पर जारी रखने की अनुमति कैसे दी गई। उन्होंने पूछा कि जब सीमा का मुद्दा पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है, तो असम द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में स्थायी निर्माण की अनुमति कैसे दी जा सकती है? जब ये घटनाएं घट रही थीं तब असम सरकार क्या कर रही थी? कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि नगालैंड प्रशासन की आपत्तियों के बाद सीमा के असम की ओर स्थित गांवों में एमजीएनआरईजीए का काम रोक दिया गया है, और सवाल उठाया कि राज्य सरकार अपने ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में क्यों विफल रही है। उन्होंने कहा कि अगर असम में वैध जॉब कार्ड रखने वाले मजदूर नगालैंड प्रशासन की आपत्तियों के कारण काम करने में असमर्थ हैं, तो असम सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? लोगों के लिए खड़े हुए बिना उसने इस तरह के हस्तक्षेप को क्यों स्वीकार किया है? उन्होंने दावा किया कि बार-बार होने वाले सीमा विवादों ने परिवारों, विशेषकर महिलाओं को, अनिश्चितता और असुरक्षा के माहौल में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि असम की सीमा के भीतर रहने वाले लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। सीमावर्ती निवासियों को भी राज्य के अन्य नागरिकों के समान ही सुरक्षा और ध्यान देने का अधिकार है। मुख्यमंत्री शर्मा पर सीधा निशाना साधते हुए, गोगोई ने उन पर *दोहरे इंजन* वाली सरकार का नेतृत्व करने के बावजूद सीमा मुद्दे पर कमजोर रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री दिल्ली में काम करवाने में सक्षम एक सशक्त नेता के रूप में अपनी छवि पेश करते हैं। लेकिन जब सीमावर्ती इलाकों में असम की भूमि और लोगों की रक्षा की बात आती है, तो वे मानो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। दोहरी इंजन वाली सरकार के साथ, लोगों को त्वरित समाधान की उम्मीद थी, लेकिन समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। गोगोई ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं ने सीमावर्ती निवासियों के बीच इस आशंका को बल दिया है कि असम की भूमि के कुछ हिस्से अंततः नगालैंड को सौंप दिए जा सकते हैं।

राज्य के छह समुदायों को ...

से संबंधित मुद्दे उठे और उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र और असम सरकार आदिवासी कल्याण से संबंधित लंबित मामलों को सुलझाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बैठक में कई प्रमुख आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई, जिनमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए), प्रधानमंत्री वन धन योजना, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं और आदिवासी समुदायों के समावेशन और सुधार से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। ओराम ने कहा कि समीक्षा में राज्य भर में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से चल रही पहलों की प्रगति का आकलन किया गया। उन्होंने कहा कि आज हमने जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मंत्री रानोज पेगू के साथ हमने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के कामकाज और प्रस्तावित नए विद्यालयों की स्थिति पर चर्चा की। हमने वन धन केंद्रों की प्रगति की भी समीक्षा की और जनजातीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन और आजीविका संवर्धन पर विचार-विमर्श किया। असम में प्रधानमंत्री वन धन योजना की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, ओराम ने कहा कि राज्य भर में 490 वन धन केंद्रों की योजना बनाई गई थी, जिनमें से 350 पहले से ही चालू हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस बात पर चर्चा की कि इन केंद्रों को और कैसे मजबूत किया जा सकता है ताकि आदिवासी समुदायों को स्थायी आजीविका के अवसर और उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त हो सके। बैठक में आदिवासी गांवों में जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे व्यापक आदिवासी विकास कार्यक्रम, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत, आवास, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तपेदिक की जांच और कई अन्य आवश्यक सेवाओं को कवर करते हुए लगभग 27 परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। असम में कार्यक्रम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, और हमने इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की, ओराम ने कहा। आदिवासी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के अलावा, अधिकारियों ने असम के आदिवासी समुदायों की समृद्ध कला, संस्कृति और पारंपरिक कलाकृतियों को संरक्षित और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित आदिवासी संग्रहालय पर भी चर्चा की। बैठक में संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत आदिवासी समुदायों को शामिल करने और उनमें सुधार लाने से संबंधित लंबित प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई।

2027 से हर केस ...

आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। न्याय संहिता के लागू होने में यानि नए कानून को लागू करने के दो साल बाद हरियाणा, गोवा, असम, चंडीगढ़, पंजाब टॉप परफार्मिंग स्टेट हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक तीन नए कानून देशभर में लागू होने के बाद न्यायिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। केस इन्वेस्टिगेशन का एवरेज टाइम पचीस परसेंट कम हुआ है। बहुत सहजता से जीरो एफआईआर दर्ज की जा रही है। ज्यादातर डिजिटल एफआईआर है। केस का टाइमलाइन के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जारी है। केस का टाइमलाइन सेंट्रलाइज हो गया है। साइंटिफिक और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से लागू हो गया है। पूरे न्याय संहिता का इंप्लीमेंटेशन सिटिजन सेंट्रिक लागू हो चुका है। तीन नए कानून देश में लागू होने के बाद बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। महज दो सालों में 74.66 लाख एफआईआर दर्ज की गई। साठ दिन में चार्जशीट दाखिल करने की दर पिछले करीब दो साल में 50 फीसदी से बढ़कर 67 फीसदी हो गई है। इसके अलावा यौन अपराधों में चार्जशीट दाखिल करने की दर दो सालों में 44 परसेंट से बढ़कर 75 परसेंट हो गई है।

सड़क सुरक्षा सरकार ...

पहुंचाने वाले को पुलिस या कानूनी झंझटों में नहीं उलझना पड़ेगा। मदद करने वाले व्यक्ति को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति का किसी भी अस्पताल में इलाज कराने पर डेढ़ लाख रुपए तक का खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि देश में हर साल औसतन पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और करीब 1.80 लाख लोगों की मौत होती है। इन हादसों से देश की जीडीपी का लगभग तीन फीसदी नुकसान होता है। इन दुर्घटनाओं में 66 फीसदी पीड़ित 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। सड़क दुर्घटनाएं न केवल जान लेती हैं बल्कि कई लोगों को स्थायी रूप से अपंग बना देती हैं। गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के चार अहम हिस्से सड़क इंजीनियरिंग, वाहन इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और जन जागरूकता हैं। इनमें सड़क इंजीनियरिंग सबसे महत्वपूर्ण है।

चुनाव आयोग के खिलाफ ...

चुनाव से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से एकजुट हैं। इस पत्र के बारे में जयराम रमेश ने बताया कि 8 जून 2026 को *इंडिया* जनबंधन के नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने हिस्सा लिया था। उसी बैठक में यह तय हुआ था कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। ऐसे में अब इस पत्र पर विपक्षी दलों का समर्थन और बढ़ गया है।

जनरल धीरज सेठ बने ...

में आतंकवाद विरोधी बल की कमान संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली और बाद में दिल्ली के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) के रूप में कार्य किया। सेना कमांडर के रूप में, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने दक्षिण पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान दोनों की कमान संभाली है, इस तरह वे भारतीय सेना के उन गिने-चुने अधिकारियों में से एक बन गए हैं जिन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर दो परिचालन सेना कमानों की कमान संभाली है। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए भारतीय सेना के एडीजी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ने लिखा कि सेना प्रमुख (सीओएएस) का पद छोड़ने के मौके पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में औपचारिक *गार्ड ऑफ ऑनर* दिया गया। चार दशकों से ज्यादा समय का उनका शानदार करियर निःस्वार्थ सेवा, प्रेरणादायक नेतृत्व और देश के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विरासत को दर्शाता है।

पाकिस्तान के रावलपिंडी...

पुलिस ने बताया है कि 14 कैदियों को अदालत में पेशी के बाद से अदियाला जेल ले जाया जा रहा था। इसी बीच मौके की ताक में बैठे सभी कैदी पुलिस वैन से फरार हो गए। फरार होने वाले कैदियों ने जेल की सुरक्षा में मौजूद खामियों का फायदा उठाया। घटना सामने आते ही जेल प्रशासन, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है और फरार कैदियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शुरुआती जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इस फरारी में किसी जेल कर्मचारी की लापरवाही या अंदरूनी मिलीभगत तो नहीं थी। जानकारी के मुताबिक, कैदियों से भरी वैन को जब जांच के लिए रोका गया, तो उसी वक्त कैदियों में पुलिस अधिकारियों की आंखों में मिर्ची फेंक दी और फरार हो गए। जिसके बाद से तुरंत सभी को ढुंढने के लिए जद्दोजहत करना पड़ा, इस दौरान 14 में से 4 कैदियों को दोबारा से पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी 10 की तलाश जारी है।

45 मिलियन लोगों पर...

में और क्या-क्या आरोप? अप्रैल महीने में कई विकासशील देशों ने सब्सिडी, कीमत की सीमा तय करने, टैक्स में कटौती और मांग को नियंत्रित करने वाले उपायों के जरिए परिवारों और व्यवसायों को ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से बचाने की कोशिश की है। लेकिन देशों को इसकी भारी वित्तीय कीमत चुकानी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक विकास नेटवर्क यूएनडीपी के मुताबिक आने वाले सालों में गरीबी में काफी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वैश्विक विकास की खराब स्थिति में, ऊपरी-मध्यम-आय वाले मानकों के अनुसार अतिरिक्त 1.7 करोड़ लोग गरीबी की चपेट में आ सकते हैं। गंभीर स्थिति में यह संख्या 4.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। 2026 में कॉर्बन आधारित ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स सब्सिडी के 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है और अगर तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं, तो यह 1.43 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इस झटके का असर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है।

बांग्लादेश में मंदिर के...

यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि देउरी को उनकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया गया था या नहीं। बाद में मंगलवार तड़के देउरी ओल्ड ढाका इलाके की एक सड़क पर बेहोशी का हालत में मिले। उनके दोस्तों ने उन्हें इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। डीएमसीएच पुलिस चौकी इंचार्ज मोहम्मद फारूक ने बताया कि देउरी को स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 7 बजे गंभीर हालत में अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। मंगलवार तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, देउरी खुलना डिवीजन के मागुरा जिले के रहने वाले हैं और राजधानी में एक दोस्त के साथ किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं। उनके रूममेट दुर्जॉय साहा ने बताया कि देउरी सोमवार रात करीब 11:30 बजे अपार्टमेंट से निकले थे। सूत्रों ने साहा के हवाले से कहा कि मुझे उनके फोन से कॉल आया जिसमें कुछ पैसे भेजने के लिए कहा गया। मैं पैसे नहीं भेज सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अपहरणकर्ताओं ने देउरी के परिवार वालों से भी संपर्क किया और फिरौती की मांग की। उनकी बहन जया ने बताया कि उन्हें मंगलवार तड़के करीब 1 बजे देउरी के फोन से कॉल आया, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने 30,000 बांग्लादेशी टका की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक, अपहरणकर्ताओं ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर दिया और 26,000 बांग्लादेशी टका ट्रांसफर होने के बाद देउरी को ओल्ड ढाका की एक सड़क पर छोड़ दिया गया। साहा ने बताया कि बचाए जाने के बाद देउरी ने उन्हें बताया कि उसे पकड़ने वालों ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया; आरोप है कि उन्होंने उसके कपड़े उतरवा दिए और उसे अपने परिवार वालों से पैसे मांगने के लिए मजबूर किया।

कर्नाटक में अब बिना ...

कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) डॉ. एमए सलीम ने एक कड़ा आदेश जारी किया है। कर्नाटक डीजीपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान या जानकारी देने का हक सिर्फ कुछ चुनिंदा और तय अधिकारियों के पास ही होगा। ये अधिकारी राज्य, रेंज, शहर, जिला और स्पेशल यूनिट के स्तर पर पहले से तय होंगे। इनके अलावा, बाकी सभी पुलिसकर्मियों पर पाबंदियां रहेंगी कि बिना लिखित इजाजत के कोई बयान या इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे। मीडिया की किसी डिबेट या चर्चा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और मीडिया को ऑफ-द-रिकॉर्ड या अंदाजे के आधार पर कोई जानकारी नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी कर्नाटक डीजीपी ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पुलिसकर्मी अपने पर्सनल या ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर बिना मंजूरी के ये चीजें पोस्ट या फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। कर्नाटक डीजीपी डॉ. एम.ए. सलीम के मुताबिक, कई बार अधूरी या संवेदनशील जानकारी बाहर आने से चल रही जांच प्रभावित होती है।

कामरूप मेट्रो प्रशासन ने दी भूस्खलन संवेदनशील पहाड़ों के निवासियों को चेतावनी

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को प्रशासन ने सतर्क रहने की सख्त चेतावनी दी है। ज्ञात हो कि गुवाहाटी में किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण में 366 भूस्खलन संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई है। इन स्थानों पर रहने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा लगातार चेतावनी दी जाती रही है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि अधिकांश भूस्खलन प्राकृतिक कारणों की जगह मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहे हैं, जिससे शहर की नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिकी पर अनियोजित शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। कामरूप (मेट्रो) जिला आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इसको लेकर किए गए सर्वेक्षण में चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया गया है। सर्वेक्षण में गुवाहाटी के नवग्रह, नरकासुर, नारंगी, नूनमाटी शांतिपुर, शरणिया, शुक्रेश्वर, सुनसाली फटासिल, गरभंगा, गोटानगर, हेंगराबाड़ी, जालुकबाड़ी-लंकेश्वर, काहिलीपाड़ा,

कालापहाड़, कामाख्या-नीलाचल, खानापाड़ा, खारगुली, कोईनाधरा और मालीगांव सहित 20 पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल किया गया। इनमें खारगुली में सर्वाधिक 77 संवेदनशील स्थल पाए गए। इसके बाद नूनमाटी में 40, नरेंगी में 37, खानापाड़ा में 33, मालीगांव में 31 और जालुकबाड़ी-लंकेश्वर में 30 स्थलों की पहचान की गई। अध्ययन के अनुसार 95 प्रतिशत भूस्खलन संभावित स्थल मानवजनित कारणों से प्रभावित हैं, जबकि केवल पांच प्रतिशत मामलों में प्राकृतिक कारण जिम्मेदार पाए गए। पहाड़ों की कटाई, तीव्र ढलानों पर निर्माण कार्य, जल निकासी व्यवस्था की कमी और अनियंत्रित शहरी विस्तार को ढलानों की अस्थिरता का प्रमुख कारण बताया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि 88 प्रतिशत संवेदनशील ढलानों का झुकाव 60 डिग्री तक है, जबकि सात प्रतिशत ढलानों का झुकाव 60 डिग्री से अधिक है। वहीं, 57 प्रतिशत स्थलों की ऊंचाई पांच मीटर से कम, 20 प्रतिशत की पांच से दस मीटर, 18 प्रतिशत की 11 से 15 मीटर तथा पांच प्रतिशत की 15 मीटर से अधिक पाई गई। वनस्पति आवरण के विश्लेषण में सामने आया कि 45 प्रतिशत संवेदनशील ढलानों पर किसी प्रकार का हरित आवरण नहीं है, जिससे कटाव और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। 36 प्रतिशत स्थलों पर घास और झाड़ियां मौजूद हैं, जबकि केवल 19 प्रतिशत स्थानों पर वृक्ष आवरण पाया गया, जो ढलानों को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूगर्भीय संरचना के आधार पर 62 प्रतिशत संवेदनशील ढलान चट्टान और मिट्टी के मिश्रण से बने हैं, 34 प्रतिशत केवल मिट्टी से तथा चार प्रतिशत पूरी तरह चट्टानी संरचना वाले हैं। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि 74 प्रतिशत चिन्हित स्थलों पर जन-धन की सुरक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। निगरानी और योजना निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सभी स्थलों को गूगल अर्थ पर मैप किया गया है, जिससे प्रशासन को जोखिम वाले क्षेत्रों की स्पष्ठ जानकारी मिल सकेगी। अध्ययन ने भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिए पहाड़ियों की कटाई पर कड़े नियंत्रण, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना को तत्काल लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कामरूप (मेट्रो) जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को फिर से इन संवेदनशील भूस्खलन की संभावना वाले स्थानों पर रहने वालों को चेतावनी दी गई है। देखना यह है कि इन खतरनाक स्थानों पर रह रहे लोग प्रशासन द्वारा दी जा रही लगातार चेतावनी के पति गंभीरता दिखाते हैं या नहीं।

श्रीभूमि में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर

श्रीभूमि (हिंस)। असम के श्रीभूमि जिले में मंगलवार को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से बुलडोजर अभियान चलाया। शहर के ब्रजेंद्र रोड क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माणों को नगरपालिका ने ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि कुछ लोगों ने सरकारी भूमि के साथ-साथ नालों और नालियों पर भी अतिक्रमण कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, जिससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। अभियान के दौरान ऐसे सभी अवैध निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई जिले के अभिभावक मंत्री कौशिक राय के कड़े निर्देश पर की गई। उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

जोनाई क्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी है असम सरकार : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों से आई अनियंत्रित जलधारा के कारण धेमाजी जिले के वृहत्तर जोनाई क्षेत्र में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस प्राकृतिक आपदा से कई गांवों में व्यापक नुकसान हुआ है और अनेक परिवार कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तेलाम, मिसामोरा और रामधन दिखारी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत मधुपुर, अरुण चापोरी, जामुगुड़ी सियारी, नंबर-2 उलुवानी, माजगांव तथा नंबर-2 और नंबर-3 मलान गांव बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण लोगों के घर, कृषि भूमि और आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। सरकार और जिला प्रशासन राहत, पुनर्वास तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं और कई जरूरी कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी के सहयोग, साहस और संवेदनशीलता से इस संकट पर जल्द ही काबू पाया जाएगा।

प्रथम वाहिनी एसएसबी ने किया सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के सोनापुर स्थित प्रथम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कमांडेंट सुनील कौशिक के मार्गदर्शन में आज वाहिनी मुख्यालय प्रगण में *सड़क सुरक्षा 2026* के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष का थीम सतर्क रहें, सुरक्षित रहें है। कार्यक्रम का शुभारंभ उप-निरीक्षक (एमटी) एसएल सिंह द्वारा सड़क सुरक्षा शपथ के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ सड़क पर अपनी व दूसरों की सुरक्षा भी हमारा कर्तव्य है। एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार को उजाड़ सकती है। अत: सभी कार्मिक हेलमेट, सीट बेल्ट एवं यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें। इस कार्यक्रम में वाहिनी के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, एवं जवानों उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उप-निरीक्षक सिंह द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। उन्होंने बताया कि सप्ताह भर बटालियन द्वारा विभिन्न स्कूलों एवं गांवों में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। *दुर्घटना से देर भली* के संदेश के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

जनजातीय कल्याण योजनाओं की प्रगति की गुवाहाटी में हुई समीक्षा

गुवाहाटी (हिंस)। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम की अध्यक्षता में मंगलवार को गुवाहाटी में मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के कल्याण एवं विकास से संबंधित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति का आकलन करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तय करना था। बैठक में असम सरकार के मंत्री डॉ. रणोज पेगू सहित केंद्रीय एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य में संचालित जनजातीय कल्याण योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन तथा आधारभूत संरचना से जुड़े विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित निगरानी तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान जनजातीय समुदायों

के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा के अवसरों का विस्तार, रोजगार के नए साधनों का सृजन, कौशल विकास कार्यक्रमों को गति देने तथा दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का आह्वान किया। बैठक के अंत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के साथ जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने तथा कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की गई।

राज्य में अवैध आरा मिलों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू

गुवाहाटी (हिंस)। असम के वन मंत्री जयंत मल्लबरुवा ने मंगलवार को राज्यभर में संचालित अवैध आरा मिलों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी अवैध आरा मिलों की पहचान कर उन्हें जब्त और स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अवैध आरा मिलें संचालित होती पाई जाएंगी, वहां के रेंज अधिकारी और प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लाइसेंस प्राप्त आरा मिलों का भी सघन निरीक्षण किया जाएगा ताकि वे लाइसेंस की शर्तों और वैध दस्तावेजों के अनुरूप ही संचालित हों। मंत्री ने लोगों से अभियान में सहयोग की अपील करते हुए अवैध आरा मिलों तथा वन अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जानकारी गोपनीय रूप से हेल्पलाइन नंबर 94352-04444 पर देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार असम के वनों की सुरक्षा के लिए अवैध कटाई और लकड़ी के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।

फर्जी डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करने के आरोपी की न्यायिक हिरासत में मौत

कोकराझाड़ (हिंस)। फर्जी डॉक्टर बनकर चिकित्सा कार्य करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति की मंगलवार तड़के कोकराझाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान रवींद्र चंद्र नाग के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, काजलगांव पुलिस ने 25 जून को असम काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर नाग को ढ़ालीगांव से गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वह स्वयं को डॉक्टर बताकर चिकित्सा कार्य कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे उसी दिन अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में कोकराझाड़ जेल भेज दिया गया। मंगलवार तड़के जेल के भीतर नाग की तबीयत अचानक बिगड़ गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसे हृदय संबंधी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। जेल प्रशासन ने तत्काल उसे गंभीर अवस्था में कोकराझाड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया, लेकिन सुबह लगभग 7:30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि न्यायिक हिरासत में हुई इस मृत्यु के संबंध में आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी की जाएंगी।

सोनारी में रेलवे का व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान

चराईदेव (हिंस)। असम के सोनारी के सफ्राई क्षेत्र में मंगलवार को रेलवे प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान रेलवे भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय भवनों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, रेलवे की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

रंगिया में पुरी की तर्ज पर मनाया जा रहा महाप्रभु रथ यात्रा महोत्सव

रंगिया (विभास)। रंगिया के पूब सीतारा स्थित महाप्रभु श्रीश्री जगन्नाथ व बुढ़ागोसाईं थान मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी लगभग महीने भर चलने वाले महाप्रभु के भव्य रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियां व आयोजन की धूम हैं। रथ यात्रा के सभी कार्यक्रमों को उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के नियमों के अनुसार ही आयोजित किया जा रहा है। विशेष बात यह है कि पुरी से आए विद्वान पंडितों द्वारा मंदिर के सभी वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। आयोजन समिति से मिली जानकारी के अनुसार, इस महीने भर के उत्सव के अंतर्गत 28 जून को महिला श्रद्धालुओं के विशेष सहयोग से अनुष्ठानिक रूप से *पानी तोला* (पवित्र जल संग्रहण) का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। 29 जून को *स्नान यात्रा* का आयोजन किया गया, जिसमें उसी पवित्र संग्रहित जल से महाप्रभु को श्रद्धापूर्वक स्नान कराया गया। इसके बाद 16 जुलाई को मुख्य रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस विशेष दिन सुबह से ही विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके बाद दोपहर बाद भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र (बलराम) और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथ पर सवार होकर रंगिया नगर का भ्रमण करेंगे। नगर परिक्रमा के बाद तीनों देवी-देवताओं को उनकी मौसी का घर माने जाने वाले रंगिया के श्रीश्री राधाकृष्ण मंदिर लाया जाएगा, जहां वे सात दिनों तक विश्राम करेंगे। 20 जुलाई को हेरा पंचमी लक्ष्मी पूजा।

एजार-सोनारू के पेड़ों से हरित होगा नगांव-बटद्रवा मार्ग

नगांव (निसं)। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की पवित्र जन्मस्थली बटद्रवा थान तक जाने वाले पूरे मार्ग को आकर्षक और हरित स्वरूप देने के उद्देश्य से नगांव जिला प्रशासन ने एक नई पर्यावरणीय पहल शुरू की है। इसके तहत नगांव शहर से ऐतिहासिक बटद्रवा धाम तक सड़क के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर सुंदर, शीतल एवं प्रकृति-अनुकूल वातावरण विकसित किया जाएगा। जिला प्रशासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत मार्ग के दोनों ओर कृष्णचूड़ा, राधाचूड़ा, एजार, सोनारू तथा नाहर जैसे स्थानीय एवं आकर्षक वृक्ष लगाए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ तीर्थ मार्ग की प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाना है। खागरीजान विकास खंड

के सहयोग से आयोजित इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ बटद्रवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रूपक शर्मा तथा जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने शांतिजान बाजार में किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रूपक शर्मा ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिक वातावरण के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मार्ग उपलब्ध कराना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि यह वृक्षारोपण अभियान केवल सड़क की सुंदरता ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से इन पौधों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करने का आग्रह किया। जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि के इस दौर में ऐसे हरित परियोजनाओं का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। स्थानीय प्रजाति के वृक्षों से मार्ग को विकसित करने से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी तथा यह मार्ग असम की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत का प्रतीक बनेगा। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों तथा स्वयं सहायता समूहों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में यह मार्ग प्रत्येक तीर्थयात्री और पर्यटक के लिए अत्यंत आकर्षक बन जाएगा। कार्यक्रम में जिला परिषद की सभानेत्री गीतांजलि हजारिका, नगांव जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिकारिया, नगांव वन प्रभागीय अधिकारी सुहास कदम, खागरीजान विकास खंड के खंड विकास अधिकारी प्राणजीत दत्ता, असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नगांव जिला परियोजना निदेशक शंखप्रबाल शांडिल्य, समाजसेवी सुर्वण सिंह, श्रीमंत शंकरदेव संघ के प्रधान सचिव कुशल ठाकुरिया, संघ की नगांव जिला समिति के पदाधिकारी, बटद्रवा थान प्रबंधन समिति के सदस्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।

मातृभूमि के वीर सपूत कैप्टन जिंटू गोगोई को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने शहीद दिवस के अवसर पर मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिक कैप्टन जिंटू गोगोई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि देश की सुरक्षा और मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए कैप्टन जिंटू गोगोई का सर्वोच्च बलिदान अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि असम और भारत माता के इस पराक्रमी वीर सपूत का त्याग सदैव असमवासियों तथा पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने शहीद दिवस पर कैप्टन जिंटू गोगोई को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि जिंटू गोगोई (21 नवंबर, 1970 को जन्म, 30 जून, 1999 को निधन), भारतीय सेना की 17वीं गढ़वाल राइफल्स के एक अधिकारी थे। उन्हें 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन में लड़ाई में दिखाए गए साहस और बहादुरी के लिए मरणोपरांत *वीर चक्र* से सम्मानित किया गया, जो युद्ध के समय दिया जाने वाला भारत का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है।

बोड़ोलैंड यूनिवर्सिटी ने एनईपी 2020 के तहत चौथे वर्ष के एफवाईयूजीपी दिशा-निर्देश जारी किए

कोकराझाड़ (विभास)। बोड़ोलैंड यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के चौथे वर्ष के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क 2022 और असम सरकार के मई 2023 के संशोधित मॉडल फ्रेमवर्क के अनुरूप तैयार किए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी. एल. आहूजा ने दिशा-निर्देशों को जारी करते हुए कहा कि एफवाईयूजीपी का चौथा वर्ष, विशेष रूप से *ऑनर्स* और *ऑनर्स विद रिसर्च* पाथवे, एनईपी 2020 के उस विजन को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य स्नातक स्तर पर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह ढांचा विश्वविद्यालय के सभी संबद्ध कॉलेजों में गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करेगा। शैक्षणिक रजिस्ट्रार डॉ. मंजिल बसुमतारी ने बताया कि यह व्यापक फ्रेमवर्क निम्नलिखित पहलुओं को कवर करता है: कार्यक्रम के दौरान रेक्टर प्रो. जतिन सरमाह, रजिस्ट्रार डॉ. प्रहलाद बसुमतारी, विभिन्न संकायों के डीन, विभागाध्यक्ष और बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया कि ये दिशा-निर्देश न केवल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, बल्कि बोड़ोलैंड यूनिवर्सिटी के अकादमिक परिवेश को वैश्विक मानकों के समकक्ष ले जाने में भी सहायक सिद्ध होंगे।

कोकराझाड़ : पत्रकारों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित

कोकराझाड़ (विभास)। प्रेस क्लब कोकराझाड़ ने कोकराझाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सहयोग से मंगलवार को पत्रकारों के लिए एक नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन बीटीसी के स्वास्थ्य कार्यकारी सदस्य डेरहासत बसुमतारी ने किया। शिविर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम ने उपस्थित मीडिया कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें चिकित्सीय परामर्श दिए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के बीच निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच

के लिए प्रोत्साहित करना था। आयोजकों ने कहा कि पत्रकार अक्सर व्यस्त दिनचर्या और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, जिसके कारण वे अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। यह शिविर उन्हें अपनी सेहत के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। कोकराझाड़ के कई पत्रकारों ने इस शिविर में भाग लिया और विभिन्न स्वास्थ्य जांचें करवाईं।

संपादकीय

वचनबद्धता का रिपोर्ट कार्ड

बड़े सोच के पैरामीटर भी बड़े करने होंगे, वरना धरातल पर आकर योजनाओं का बिखराव ही होगा। हिमाचल की दृष्टि में माई बाप मानने की संगत और ऐसी सियासत पैदा हुई है कि सारे हुजूर सत्ता में नजर आते हैं। इसलिए यहां भी वोट का आरक्षण फरियादी हो कर गारंटियां मांगता है। यहां निर्णायक होने की वजह सरकार से प्राप्तियां हैं और इसीलिए समीक्षाएं अक्सर फेस वैल्यू पर होती हैं। हिमाचल के सामर्थ्य का दोहरा विभाजन है। एक ओर हम यह चाहते हैं कि सरकारें कर्ज न उठाएं, तो दूसरी ओर मुफ्त बंटवारे का फर्ज निभाएं। ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच केवल एक जीत का अंतर सारे नक्शे नहीं बदल पाता, बल्कि वही खातों का बहाव बरकरार रहता है। बहरहाल चुंबकीय आकर्षण यह कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछड़ेपन के पत्तन तोड़ कर बड़ा भंगाल पहुंचे, तो कारवां महिलाओं तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने अपने कर्म और फर्ज का युक्तिकरण करते हुए अतिदुरुह क्षेत्रों के पत्थर तोड़े हैं और इसी कड़ी को बड़ा भंगाल से जोड़ते वह वचनबद्धता का रिपोर्ट कार्ड टांग देते हैं। सवाल यह भी है कि सरकार के मायने सिर्फ इतने ही बचे हैं कि हिमाचली समाज अपने ही स्वार्थ की आरती उतारे। बड़ा भंगाल में पंद्रह सौ रुपए की पुड़िया में सदियों का मर्म छुपा है, कोई ताकीद कर के कि इस तरह रहम बहता है। कई दृष्टि से हिमाचल में बड़ा भंगाल अति पिछड़ा हो जाता है। जब सर्दियों के मौसम में बर्फ की सफेद चादर के नीचे दर्द की पट्टी उभरती है, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से यह क्षेत्र लाहौल-किन्नौर से अति दुष्कर नजर आता है, तो क्या कोई एक सुरंग यहां के पथ को हमेशा बहाल नहीं कर सकती। बड़ा भंगाल की गुल्लक बैजनाथ में आकर खाली होती है, तो इसे हमेशा भरा हुआ रखने के लिए मुख्यमंत्री का शपथपत्र काम आएगा। दरअसल आर्थिक दुरुहता के खिलाफ राज्य की प्राथमिकताएं कम विकसित क्षेत्रों पर आकर ही तय होंगी और इस दृष्टि से रात्रि विश्राम की पहल करके मुख्यमंत्री सुक्खू ने पांगी-बड़ा भंगाल जैसे इलाकों की नब्ज टटोली है। इसी परिप्रेक्ष्य में कभी बीबीएन जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम, कई खामियों को दुरुस्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर शिमला की तर्ज पर जिला मुख्यालयों, प्रमुख शहरों व धार्मिक नगरियों में सुबह की सैर करें, तो मालूम होगा कि कितने आवारा पशु शहरों के अमन को बर्बाद कर रहे हैं या बंदरों के नाच ने नागरिकों का जीना हराम किया है। आश्चर्य यह कि जिलाधीश कार्यालयों में जहां फूल उगने चाहिएं, वहां खड़पतवार चिढ़ा रहे होते हैं। ट्रैफिक जाम में कई कस्बे फंसे रहते हैं। इतना ही नहीं जो क्षेत्र स्थानीय निकायों के हवाले होने चाहिएं, वहां पंचायतें सिर्फ नागरिकों को मुजरिम बना रही होती हैं। उदाहरण के लिए छावनी क्षेत्रों से आजाद होकर अगर दशकों की शहरी परिपाटी को पंचायतों में बांटा जा रहा है, तो यह लज्जाजनक उपलब्धि है। सबसे बड़े योल छावनी से नागरिक क्षेत्र बाहर करके न जाने किस सियासत की संतुष्टि हुई, लेकिन अब चार पंचायतों में विघटित क्षेत्र गंदगी, नागरिक सुविधाओं की अफरातफरी और मूलभूत सुविधाओं की योजनाओं में दरिद्र हो गए। आजादी के पहले से योल छावनी प्रशासन इन क्षेत्रों में सुरक्षित पानी, साफ आबोहवा और व्यवस्थित जीवन की गारंटी दे रहा था, तो अब गांव की दहलीज पर आटा गीला करके क्या मिलेगा। हिमाचल की प्रगति, आर्थिक दुरुहता और पिछड़ेपन को दूर करके साबित होगी, तो धर्मशाला से चंद कदम दूर योल छावनी के पिछड़े ग्राम नगर निगम की परिधि में समाहित होने चाहिएं।

हिमाचल की दृष्टि में माई बाप मानने की संगत और ऐसी सियासत पैदा हुई है कि सारे हुजूर सत्ता में नजर आते हैं। इसलिए यहां भी वोट का आरक्षण फरियादी हो कर गारंटियां मांगता है। यहां निर्णायक होने की वजह सरकार से प्राप्तियां हैं और इसीलिए समीक्षाएं अक्सर फेस वैल्यू पर होती हैं। हिमाचल के सामर्थ्य का दोहरा विभाजन है। एक ओर हम यह चाहते हैं कि सरकारें कर्ज न उठाएं, तो दूसरी ओर मुफ्त बंटवारे का फर्ज निभाएं। ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच केवल एक जीत का अंतर सारे नक्शे नहीं बदल पाता, बल्कि वही खातों का बहाव बरकरार रहता है। बहरहाल चुंबकीय आकर्षण यह कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछड़ेपन के पत्तन तोड़ कर बड़ा भंगाल पहुंचे, तो कारवां महिलाओं तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने अपने कर्म और फर्ज का युक्तिकरण करते हुए अतिदुरुह क्षेत्रों के पत्थर तोड़े हैं और इसी कड़ी को बड़ा भंगाल से जोड़ते वह वचनबद्धता का रिपोर्ट कार्ड टांग देते हैं। सवाल यह भी है कि सरकार के मायने सिर्फ इतने ही बचे हैं कि हिमाचली समाज अपने ही स्वार्थ की आरती उतारे। बड़ा भंगाल में पंद्रह सौ रुपए की पुड़िया में सदियों का मर्म छुपा है, कोई ताकीद कर के कि इस तरह रहम बहता है। कई दृष्टि से हिमाचल में बड़ा भंगाल अति पिछड़ा हो जाता है। जब सर्दियों के मौसम में बर्फ की सफेद चादर के नीचे दर्द की पट्टी उभरती है, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से यह क्षेत्र लाहौल-किन्नौर से अति दुष्कर नजर आता है, तो क्या कोई एक सुरंग यहां के पथ को हमेशा बहाल नहीं कर सकती।

सरकारी नीतियों ने भी आम आदमी के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया

नागरिकता के दस्तावेजों पर इतना भ्रम ठीक नहीं..

उमेश चतुर्वेदी

पिछले कुछ वर्षों में पासपोर्ट हासिल करना आसान हो गया है। इसकी वजह तकनीकी क्रांति तो है ही, लेकिन सरकारी नीतियों ने भी आम आदमी के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया है। पासपोर्ट हासिल करने के कठिन दौर से लेकर आसानी से प्राप्त होने के मौजूदा दौर में, आम नागरिक इसे अपनी नागरिकता का एक वैध दस्तावेज मानता रहा है। लेकिन पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के पासपोर्ट को लेकर दिए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस अधिकारी के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं। जहां पासपोर्ट हासिल करने को चार धाम यात्रा जैसी उपलब्धि माना जाता रहा हो, जहां किसी व्यक्ति की पहचान के लिए मजबूत सरकारी दस्तावेज माना जाता रहा हो, वहां ऐसा बयान आएगा तो विवाद होगा ही। तो विवाद हो रहा है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट नागरिकता का वैध दस्तावेज नही है तो फिर कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता के लिए क्या सबूत पेश करे। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के शब्दों से गुजरें तो विदेश मंत्रालय के अधिकारी का कहना गलत भी नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में मतदाता सूचियों के विशेष और गहन परीक्षण के दौरान जब घोषित कर दिया गया कि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना उसकी नागरिकता के सबूत नहीं है और अब पासपोर्ट भी नहीं रहा, तो फिर भारतीय नागरिक क्या करे। जरूरत पड़ने पर वह कैसे साबित करे कि वह भारतीय नागरिक है। इस आधार पर तो देश के ज्यादातर लोग अपनी नागरिकता को तो साबित ही नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज के दौर की तमाम लड़ाइयों का बुनियादी और मजबूत आधार चूंकि नैरेटिव बन गया है तो यह भी साबित करने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है। इसके लपेटे में मोदी समर्थक ताकतें भी आएंगी, भारतीय जनता पार्टी पर तो खैर सवाल उठेगा ही। इस नैरेटिव को खड़ा होने से पहले ही जरूरी है कि नागरिकता के वैध दस्तावेज को लेकर जारी भ्रम को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अन्यथा भ्रम का यह कुहासा जितना फैलेगा, वह आम नागरिक के मन में व्यवस्था के प्रति गुस्सा और क्षोभ भरेगा। इससे तनाव बढ़ाने वाली ताकतों को भी मौका मिलेगा। पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने जो कहा है, वह गलत भी नहीं है। अपने देश में भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी किया जाता है। जबकि भारत में नागरिकता की व्याख्या और प्रमाणिकता के लिए भारतीय नागरिकता कानून 1955 है। पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 के मुताबिक, अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है। बस शर्त यह

पासपोर्ट हासिल करने के कठिन दौर से लेकर आसानी से प्राप्त होने के मौजूदा दौर में, आम नागरिक इसे अपनी नागरिकता का एक वैध दस्तावेज मानता रहा है। लेकिन पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के पासपोर्ट को लेकर दिए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस अधिकारी के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं। जहां पासपोर्ट हासिल करने को चार धाम यात्रा जैसी उपलब्धि माना जाता रहा हो, जहां किसी व्यक्ति की पहचान के लिए मजबूत सरकारी दस्तावेज माना जाता रहा हो, वहां ऐसा बयान आएगा तो विवाद हो रहा है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट नागरिकता का वैध दस्तावेज नहीं है तो फिर कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता के लिए क्या सबूत पेश करे।

होगी कि सरकार को ऐसा लगे कि उसके लिए पासपोर्ट जारी करना व्यापक जनहित में जरूरी है। इस कानून से साफ है कि पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग अलग चीजें हैं। बेशक भारतीय पासपोर्ट सिर्फ भारतीयों को ही मिलता है, लेकिन यह पत्थर की लकीर जैसा नियम नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20 भारत सरकार को छूट देती है कि व्यापक जनहित में वह भारतीय नागरिक ना होने के बावजूद किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी कर सकती है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बयान पर भले ही विवाद खड़ा हुआ हो, लेकिन पासपोर्ट के जरिए नागरिकता प्रमाणित करने के तीन अभियुक्तों समेत चार लोगों के दावे को बांबे हाईकोर्ट 2013 में ही खारिज कर चुका है। उन्होंने अपनी नागरिकता के लिए पासपोर्ट पेश किया था। बांबे हाईकोर्ट ने दो सितंबर 2013 के अपने फैसले में साफ कर दिया था कि अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है तो पासपोर्ट को अपनी नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं पेश कर सकते। वैसे आधार कार्ड का कानून भी मानता है कि आधार कार्ड सिर्फ निवास और पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। आधार कानून 2016 की धारा में साफ लिखा है कि आधार कार्ड से नागरिकता की बजाय सिर्फ निवास स्थान और पहचान प्रमाणित होता है। इसकी वजह यह है कि आधार कानून के तहत 182 दिनों तक भारत में लगातार रहने वाले व्यक्ति को सरकार चाहे तो आधार कार्ड जारी कर सकती है। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय भी इसे नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर चुका है। इसी तरह पैन कार्ड के लिए भी व्यवस्था दी गई है। पैन कार्ड का कानूनी आधार है कि व्यक्ति अर्जन कर रहा है और टैक्स दे रहा है। आधुनिक विश्व व्यवस्था की एक खामी यह है कि यहां कानून की भाषा अलग होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कानूनी भाषा जटिल होती है और उसके शब्द जाल को आम आदमी नहीं समझ पाता। इसी आधार पर उसकी अवधारणाएं विकसित होती हैं और फिर वह किसी विषय का व्यवस्था को लेकर अपनी राय बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी को इन जटिलताओं की समझ है, शायद यही वजह है कि उनके कार्यकाल में देश के सैकड़ों गैरजरूरी कानूनों को या तो रद्द किया गया है या फिर कुछ नए संदर्भों वाले कानूनों में समाहित कर दिया गया है। आज के दौर में नागरिकता के दस्तावेज के रूप जब पासपोर्ट, आधार कार्ड , पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को आखिरी और अंतिम प्रमाण मानने से इनकार किया जाता है तो अपनी लोक और आम धारणा के चलते आम आदमी इसके विरोध में उतर आता है। यही वजह है कि जब मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर के दौरान इन दस्तावेजों को आखिरी दस्तावेज मानने से इनकार किया गया तो इसका विरोध शुरू हुआ था। कुछ इसी अंदाज में पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बयान पर भी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूछ लिया है कि पासपोर्ट बनाने से पहले पुलिस जब व्यक्ति का सत्यापन करती है तो आखिर वह किसका सत्यापन करती है और क्यों करती है? उनका यहां तक कहना है कि इससे लोगों के मन में यह भी संदेह उत्पन्न हो सकता है कि गैर भारतीयों को भी पासपोर्ट दिए जा रहे हैं? इन पंक्तियों के लिखे जाने तक भारत सरकार की ओर से नागरिकता के प्रमाण को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब पासपोर्ट मान्य नहीं, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर भरोसा नहीं और पैन कार्ड मान्य नहीं तो फिर आम नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे साबित करे। निश्चित तौर पर इसका भी सरकारी व्यवस्था में है। 20 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा था, 'जन्म की तारीख और जन्म-स्थान से जुड़े कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि, ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।' इसमें रिलीज में कहा गया था कि जन्म की तारीख और जन्म स्थान से जुड़े कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि, इन दस्तावेजों के बारे में आखिरी रूप से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसमें वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, इंश्योरेंस के कागजात, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर से जुड़े दस्तावेज या सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ऐसे ही अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में और भी दस्तावेज शामिल किए जा सकते हैं ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को बेवजह परेशानी न हो। बेशक कानून की भाषा अलग होती है और लोक का शब्द संसार अलग, लेकिन दोनों के बीच संतुलन होना ही चाहिए। लोक की समझ अपने तंत्र के लिए बेहतर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि लोक और कानून की भाषा के बीच के अंतर को पाट लिया जाए। अन्यथा गलतफहमियां होती रहेंगी और आखिरकार इससे नुकसान लोकतंत्र का होगा।

देश दुनीया से

क्या हम विकास और विनाश के बीच संतुलन साध पाएंगे?

वेनेजुएला में हाल में आए भीषण भूकम्प ने केवल एक देश को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को झकझोर दिया है। मृतकों और लापता लोगों की संख्या समय के साथ बदलती रही हो, लेकिन त्रासदी की भयावहता निर्विवाद है। हजारों परिवार अपने प्रियजनों को खोने की असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक अवसर पर पूरी दुनिया संवेदना व्यक्त करती है, राहत सामग्री भेजती है, सहायता अभियान चलाती है, लेकिन एक प्रश्न बार-बार हमारे सामने खड़ा हो जाता है-क्या हम हर बड़ी आपदा से कोई स्थायी सबक सीखते हैं या फिर कुछ दिनों की चर्चा और शोक के बाद सब कुछ भुलाकर पुनः उसी लापरवाह विकास-यात्रा एवं प्रकृति की घोर उपेक्षा पर निकल पड़ते हैं? प्राकृतिक आपदाएं कभी कैलेंडर देखकर नहीं आतीं। वे न देश चुनती हैं, न मौसम और न समय। जब धरती कांपती है, नदियां उफान पर आती हैं, पहाड़ दरकते हैं या समुद्र विकराल रूप धारण कर लेता है, तब विकास के बड़े-बड़े दावे, ऊंची-ऊंची इमारतें और तकनीकी उपलब्धियों का अहंकार कुछ ही क्षणों में धराशायी हो जाता है। ऐसे समय में किसी देश की वास्तविक शक्ति उसकी आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि उसकी पूर्व तैयारी, संवेदनशील शासन व्यवस्था और जागरूक नागरिक होते हैं। वेनेजुएला की त्रासदी ने एक सकारात्मक पक्ष भी सामने रखा। आधुनिक तकनीक ने कुछ क्षेत्रों में लोगों को भूकम्प के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले चेतावनी दी। सुनने में यह समय बहुत कम प्रतीत होता है, लेकिन आपदा की घड़ी में यही कुछ सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय कर सकते हैं। विज्ञान इस दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे प्रारंभिक चेतावनी तंत्र अधिक सटीक, अधिक तेज और अधिक व्यापक बनाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। भारत के लिए यह विषय केवल एक अंतरराष्ट्रीय समाचार नहीं है। हमारा देश स्वयं भूकम्प, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने, चक्रवात और सुनामी जैसी अनेक

प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। 1993 का लातूर भूकम्प, 2001 का भुज भूकम्प, 2004 की सुनामी, 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2023 की जोशीमठ भू-धंसाव की घटनाएं तथा हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित हैं। इन सभी घटनाओं का एक ही संदेश है-प्रकृति को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैज्ञानिक आज भी यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि किस दिन, किस समय और किस स्थान पर भूकम्प आएगा, लेकिन वे वर्षों से यह चेतावनी अवश्य देते रहे हैं कि भारत का लगभग साठ प्रतिशत भूभाग किसी न किसी स्तर के भूकम्पीय जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। हिमालयी क्षेत्र, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर-पूर्व, गुजरात और अनेक अन्य क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यदि भूकम्प की सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है, तो भी पूर्व तैयारी पूरी तरह संभव है। दुर्भाग्य यह है कि हम तैयारी की अपेक्षा आपदा के बाद राहत और पुनर्वास पर अधिक ध्यान देते हैं। आज देश के लगभग हर शहर में कंक्रीट के विशाल जंगल तेजी से खड़े हो रहे हैं। बहुमंजिला आवासीय परिसर, व्यावसायिक भवन, गगनचुंबी टावर और स्मार्ट सिटी विकास की नई पहचान बन चुके हैं। मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और अब जयपुर जैसे शहर भी ऊंची-ऊंची इमारतों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इन भवनों की मजबूती केवल सामान्य परिस्थितियों के लिए है या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए भी? किसी भी भवन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब धरती कांपती है, जब अचानक बाढ़ आती है, जब तेज हवाएं चलती हैं या जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। यदि उस समय भवन लोगों की जान बचा सके, तभी उसे वास्तविक विकास का प्रतीक माना जाना चाहिए। केवल ऊंचाई, चमक-दमक और आधुनिक सुविधाएं किसी भवन को सुरक्षित नहीं बनातीं। भारत में भूकम्परोधी निर्माण के लिए मानक और नियम मौजूद हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। समस्या नियमों की कमी नहीं, बल्कि उनके अनुपालन की है। क्या प्रत्येक बहुमंजिला इमारत वास्तव में उन्हीं मानकों के अनुरूप निर्मित हो रही है? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच होती है? क्या निर्माण के बाद संरचनात्मक सुरक्षा का स्वतंत्र परीक्षण किया जाता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, तो चिंता स्वाभाविक है। निर्माण क्षेत्र में बढ़ती अनियमितताओं और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। अनेक बार भू-माफिया, बिल्डर लॉबी और लाभ-लोलुप तत्व पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए हरित क्षेत्रों, जलाशयों, नदी तटों और भू-संवेदनशील क्षेत्रों तक में निर्माण कर देते हैं। बाद में यही निर्माण किसी त्रासदी का कारण बनते हैं। नोएडा में अवैध रूप से निर्मित सुपरटेक ट्विन टावरों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त किया जाना इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि कोई निर्माण अवैध था, तो उसे बनने की अनुमति किसने दी? निर्माण पूरा होने तक प्रशासन मौन क्यों रहा।

आप का नजरीया

समझौता संभव नहीं...

आखिर राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान क्या चाहते हैं? वे युद्ध को समाप्त करने के पक्षधर हैं अथवा युद्धविराम का ढोंग करते रहना चाहते हैं? दुनिया की पतली आर्थिक स्थितियों और ऊर्जा-खाद्य संकट के कोहराम के लिए दोनों ही देश ज़िम्मेदार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट लिखी है, जिसके भाषायी मायने साफ हैं कि उन्होंने मान लिया है कि ईरान मानने लायक नहीं है, लिहाजा अब सेना के जरिए काम पूरा करना पड़ेगा। यदि ऐसा करना पड़ा, तो ईरान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। पलटबयान में ईरान भी कम नहीं है। उसके प्रवक्ता भी खूब धमकियां देते हैं। अप्रत्याशित हथियारों की बात करते हैं। समझौते के सहमति-पत्र पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने दस्तखत किए थे। उसकी अपनी राष्ट्रीय और द्विपक्षीय महत्ता और गरिमा होती है, लेकिन ईरान में कट्टरपंथियों और आईआरजीसी का एक तबका ऐसा है, जो युद्ध खत्म करने के खिलाफ है। और कितना बर्बाद, खंडहर होना चाहता है ईरान? उसकी 40 फीसदी से ज्यादा आबादी गरीबी-रेखा के तले जीने को विवश है। मुद्रास्फीति 65-70 फीसदी के करीब है, लिहाजा ब्रेड, मांस, खाने-पीने की आम चीजों की कीमतें 140 फीसदी तक उछल गई हैं। अर्थव्यवस्था में 8.8 से 10 फीसदी तक की गिरावट संभावित है। यह आकलन आईएमएफ का है। ईरानी मुद्रा 'रियाल' का ऐसा ऐतिहासिक पतन हुआ है, लिहाजा लोग किश्तों पर 'रोटी' खाने को विवश हैं। युद्ध में ईरान का नुकसान करीब 270 अरब डॉलर आंका गया है, जो उसकी जीडीपी के 57 फीसदी के बराबर है। और कितना दरिद्र होगा ईरान? ताजा हालात ये हैं कि अमरीकी सेना ने ईरान के 10 मिसाइल और ड्रोन के ठिकानों पर हमले किए। उसने ईरान के रडार और सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया। पलटवार में ईरान ने कुवैत के अमरीकी वायुसेना बेस और बहरीन के अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े पर मिसाइल हमले कर उन्हें तबाह कर दिया। ईरान ने कतर में भी हमले किए, लेकिन इस बार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नहीं छुआ। शायद कोई 'मोटी डील' हो गई होगी! अमरीका ने होर्मुज के तटीय इलाकों में, केश्म द्वीप और सिरिक में, एफ-16 समेत 6 लड़ाकू विमानों से हमले किए और ईरान के 4 अहम ठिकानों को तबाह, बर्बाद करने का दावा किया। अब ईरान ने हुंकार भरी है कि होर्मुज पर उसका ही कब्जा बरकरार रहेगा। जिस जहाज, टैंकर ने उसके निर्देश नहीं माने, तो उन पर हमला कर नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यह समझौते और युद्धविराम की कौन-सी भाषा है? इन हमलों और जंगी परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अमरीका-ईरान के दरमियान एक ठोस, स्थायी समझौता संभव नहीं है। दोनों की मानसिकता ही समझौते की नहीं है, बल्कि वे अब भी कट्टर दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दोनों के बीच जिस तरह हमले बोले जा रहे हैं, वे कोई सामान्य, छुटपुट टकराव नहीं हैं, संपूर्ण युद्ध के आक्रमण हैं। शायद इस युद्ध से अमरीकी अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर उतना असर न पड़े, लेकिन युद्ध के दौरान उसके भी 14 सैनिक मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। यह पेंटागन की ही रपट है कि 42 मानवरहित विमान, ड्रोन, लड़ाकू विमान नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए। अमरीका का कुल युद्ध खर्च 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। पेंटागन ने शेष युद्ध और हथियारों के लिए 80 अरब डॉलर (करीब 6.6 लाख करोड़ रुपए) के अतिरिक्त बजट की मांग संसद से की है, लेकिन संसद ने फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। यदि युद्ध के संदर्भ में भारत का आकलन करें, तो ईरान युद्ध से भारत को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापक आर्थिक और राजकोषीय झटका लगा है। भारत करीब 88 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। जब तेल के दाम 110 डॉलर तक उछले थे, तो पेट्रोल-डीजल, एलपीजी, सीएनजी, खाद आदि के दाम भी बढ़ाए गए थे। फिलहाल उन्हें सस्ता नहीं किया गया है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट लिखी है, जिसके भाषायी मायने साफ हैं कि उन्होंने मान लिया है कि ईरान मानने लायक नहीं है, लिहाजा अब सेना के जरिए काम पूरा करना पड़ेगा। यदि ऐसा करना पड़ा, तो ईरान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। पलटबयान में ईरान भी कम नहीं है। उसके प्रवक्ता भी खूब धमकियां देते हैं। अप्रत्याशित हथियारों की बात करते हैं। समझौते के सहमति-पत्र पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने दस्तखत किए थे। उसकी अपनी राष्ट्रीय और द्विपक्षीय महत्ता और गरिमा होती है, लेकिन ईरान में कट्टरपंथियों और आईआरजीसी का एक तबका ऐसा है, जो युद्ध खत्म करने के खिलाफ है। और कितना बर्बाद, खंडहर होना चाहता है ईरान? उसकी 40 फीसदी से ज्यादा आबादी गरीबी-रेखा के तले जीने को विवश है। मुद्रास्फीति 65-70 फीसदी के करीब है, लिहाजा ब्रेड, मांस, खाने-पीने की आम चीजों की कीमतें 140 फीसदी तक उछल गई हैं। अर्थव्यवस्था में 8.8 से 10 फीसदी तक की गिरावट संभावित है। यह आकलन आईएमएफ का है। ईरानी मुद्रा 'रियाल' का ऐसा ऐतिहासिक पतन हुआ है, लिहाजा लोग किश्तों पर 'रोटी' खाने को विवश हैं। युद्ध में ईरान का नुकसान करीब 270 अरब डॉलर आंका गया है, जो उसकी जीडीपी के 57 फीसदी के बराबर है। और कितना दरिद्र होगा ईरान? ताजा हालात ये हैं कि अमरीकी सेना ने ईरान के 10 मिसाइल और ड्रोन के ठिकानों पर हमले किए।

कुछ अलग

भाषा की राजनीति

बहस का अगला विषय था- भाषा की राजनीति। कॉकरोचानंद व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, 'मनुष्य बड़ा विचित्र जीव है। अपनी भाषा बोलने वालों को पिछड़ा कहता है और अंग्रेजी भाषा में गलत बोलने वाले को आधुनिक।' साहित्य प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि ने उनका समर्थन करते हुए कहा, 'हमने देखा है कि कुछ मनुष्य 'वाटर' मांगते हैं, जबकि प्यास उन्हें पानी की ही लगी होती है।' सभा फिर हंसी से भर उठी। कॉकरोचानंद ने कहा, 'भाषा ज्ञान का माध्यम है, प्रतिष्ठा का नहीं। किंतु मनुष्य ने उसे पद, पैसा और पहचान का प्रवेश-द्वार बना दिया है।' एक छात्र ने प्रश्न किया, 'क्या अंग्रेजी सीखना गलत है?' 'कदापि नहीं।' वह बोले। 'फिर समस्या क्या है?' छात्र ने पूछा। 'समस्या तब है, जब भाषा सीखने के साथ मनुष्य स्वयं को भूलने लगे।' वह गंभीर होकर बोले। यह सुनकर सभा शांत हो गई। कॉकरोचानंद ने एक पुराना किस्सा सुनाया, 'एक बार एक युवा तिलचट्टा विदेश गया। लौटकर उसने कहा, 'अब मुझे तिलचट्टा मत कहिए, मैं इंटरनेशनल कॉकरोच हूं।' मैंने पूछा, 'बेटा, चप्पल किस भाषा में डरते हो?' यह सुनकर उसने सिर झुका लिया। संपूर्ण सभागार ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद पहचान पर चर्चा आरंभ हुई। एक प्रतिनिधि बोला, 'गुरुदेव! मनुष्य अपने शहरों, सड़कों, संस्थानों और योजनाओं के नाम दूसरी भाषाओं में बदलकर बहुत प्रसन्न होता है।' कॉकरोचानंद ने कहा, 'हां। उसे लगता है नाम बदलते ही इतिहास भी बदल जाएगा।' 'पर कुछ बदलता है?' एक अन्य ने पूछा। 'सिर्फ बोर्ड।' वह हंसते हुए बोले। सभा में तालियां बज उठीं। वह आगे कहने लगे, 'यदि अस्पताल का नाम 'आरोग्य भवन' रख देने से रोग समाप्त हो जाएं, तो चिकित्सा विज्ञान की आवश्यकता ही न रहे।' अब आधुनिकता पर बहस शुरू हुई।

दृष्टि कोण

स्कूल प्रबंधन समिति : शिक्षा की नई उम्मीद

यदि किसी राष्ट्र का भविष्य देखना हो तो उसके विद्यालयों को देखिए।' यह केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि शिक्षा का शाश्वत सत्य है। विद्यालय किसी भी राष्ट्र की आत्मा होते हैं। यहीं से संस्कार, अनुशासन, नागरिक चेतना और जिम्मेदार भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षा केवल सरकार या शिक्षकों का दायित्व नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। आज जब हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नई स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन हो रहा है, तब यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालयों में जनविश्वास, उत्तरदायित्व और सामुदायिक भागीदारी को सशक्त बनाने का सुनहरा अवसर है। भारत में विद्यालयों के प्रबंधन में जनभागीदारी का विचार नया नहीं है। अंग्रेजी शासनकाल में 1882 के हंटर आयोग ने पहली बार यह सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा के विकास में स्थानीय निकायों और समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। यद्यपि उस समय औपचारिक स्कूल प्रबंधन समितियां अस्तित्व में नहीं थीं, फिर भी यह स्वीकार किया गया कि विद्यालय केवल सरकार के भरोसे नहीं चल सकते। 1904 की भारतीय शिक्षा नीति तथा 1919 के भारत शासन अधिनियम ने भी स्थानीय संस्थाओं और समाज की भूमिका को प्रोत्साहित किया। यही वह दौर था जब अभिभावकों को विद्यालय से जोडने की सोच ने आकार लेना शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया। 1964-66 के कोठारी आयोग ने स्पष्ट कहा कि विद्यालय तभी सफल होंगे जब समाज उन्हें अपना संस्थान माने। इसी सोच के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने सामुदायिक सहयोग और समान अवसरों पर बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा 1992 के संशोधित कार्यक्रम ने विद्यालयों के प्रबंधन में अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को और अधिक महत्व दिया। आगे चलकर सर्व शिक्षा अभियान के दौरान विद्यालय शिक्षा समितियों और ग्राम शिक्षा समितियों के

माध्यम से अभिभावकों को नामांकन बढ़ाने, विद्यालय विकास और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस व्यवस्था को कानूनी आधार बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से मिला, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके तहत प्रत्येक सरकारी विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य किया गया, जिसमें अधिकांश सदस्य अभिभावक रखने का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य स्पष्ट था-विद्यालयों का संचालन जनता की भागीदारी से हो और प्रत्येक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी केवल शिक्षक की नहीं, बल्कि पूरे समाज की बने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विद्यालय को समाज का केंद्र मानते हुए शिक्षक, अभिभावक, पंचायत, पूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के बीच मजबूत साझेदारी पर बल दिया। इसी दिशा में शिक्षा मंत्रालय द्वारा मई 2026 में जारी स्कूल प्रबंधन समिति दिशा-निर्देश विद्यालय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण सुधार माने जा रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों में पारदर्शिता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, मासिक बैठकें, तीन वर्षीय विद्यालय विकास योजना, महिला प्रतिनिधित्व, सीखने के परिणामों की समीक्षा तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एकीकृत एसएमसी व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिससे विद्यालय प्रबंधन अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बन सके। हिमाचल प्रदेश लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में रहा है।

मुख्यमंत्री योगी का सपा पर प्रहार
बोले, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आज आस्था की दुहाई दे रहे

रामपुर (हिंस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रामपुर में 690 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं मुख्य रूप से मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों की हैं। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सपा नेताओं पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज बड़े आस्थावान बन रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले विकास कुछ परिवारों तक सीमित था, लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गों के लोगों को विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाती है। विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामपुर की यह धरती भगवान महाकालेश्वर महादेव, ओम नागेश्वर महादेव, कोसी मंदिर और मां बाला सुंदरी जैसे आस्था केंद्रों से समृद्ध है। आज करीब 690 करोड़ रुपए की लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं से मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र का विकास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले का रामपुर और आज का रामपुर, दोनों की तस्वीर जनता के सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब रामपुर के गरीब वाल्मीकि समाज की जमीनों पर कब्जे किए जाते थे लेकिन जब सत्ता जनता के हितों के खिलाफ काम करती है तो जनता उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देती है। रामपुर से जो संदेश निकला, वह पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचा और समाजवादी पार्टी की निरंकुशता पर जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से अंकुश लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान बना चुका है। प्रदेश सबसे अधिक रोजगार देने, किसानों को सबसे अधिक अनुदान देने, युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने, खाद्यान्न, दुग्ध, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश लगभग हर पैमाने पर सबसे निचले पायदान पर होता था, लेकिन आज अधिकांश क्षेत्रों में पहले या दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा सपा सरकार के समय केवल दो परिवारों का विकास होता था–इनमें एक था सैफई परिवार और दूसरा रामपुर का एक परिवार। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की विरासत का अपमान किया जाता था और समाजवादी पार्टी ने बहन–बेटियों की सुरक्षा के साथ भी समझौता किया। उस समय कांवड़ यात्रा तक को निकलने नहीं देने की बातें होती थीं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर भी रोक लगाई थी। योगी ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, निवेश बढ़ा है, रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और विकास का लाभ बिना भेदभाव हर वर्ग तक पहुंचाया जा रहा है। जहां डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की आवश्यकता है, वहां नए संस्थान खोले जा रहे हैं। वहीं पुराने विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकार तथा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। उ गा। मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा में सीधा संवाद करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा श्रेय प्रदेश की जनता को जाता है, जिसने विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को चुना। उन्होंने कहा कि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि और अच्छे विधायक चुने हैं, इसलिए विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। प्रदेश में बेहतर सड़कें, पुल, आधारभूत ढांचा और जनसुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व रामपुर के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, कृषि शिक्षा मंत्री बलदेव सिंह औलख, सदर विधायक आकाश सक्सेना विधान परिषद सदस्य डॉ जयपाल सिंह व्यस्त, डॉ. हरि सिंह ढिल्लो, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, जिला संगठन प्रभारी राजा वर्मा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल, भाजपा रामपुर जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला महामंत्री अर्जुन रस्तोगी आदि उपस्थित रहे।

बैंक घोटाले में सीबीआई ने आईडीएफसी व एयू स्माल फाइनेंस के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया

चंडीगढ़ (हिंस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंड गबन मामले में दो बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें आईडीएफसी के तत्कालीन एरिया हेड शमीम डार और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की मोहाली शाखा के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर चरणजीत सिंह रंधावा हैं। सीबीआई के अनुसार यह मामला हरियाणा सरकार के विभागों के फंड की हेराफेरी से जुड़ा है। आरोप है कि सरकारी विभागों के सरप्लस फंड को अनियमित तरीके से फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश दिखाकर और इस मकसद से खोले गए बैंक खातों के जरिए फर्जी लेन–देन कर सार्वजनिक धन को डायवर्ट किया गया। जांच में सामने आया कि दोनों अधिकारियों ने अपने–अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बैंक खाते खुलवाने और फर्जी लेन–देन को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। सीबीआई ने जांच के दौरान दोनों के खिलाफ आपत्तिजनक सबूत जुटाए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया है। सीबीआई ने यह जांच हरियाणा सरकार के अनुरोध पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से अपने हाथ में ली थी। यह घोटाला चंडीगढ़ के सेक्टर–32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में हुआ। इस मामले में हरियाणा सरकार के 8 विभागों के करीब 504 करोड़ रुपए फर्जी या गैर–मौजूद फिक्स्ड डिपॉजिट और डेबिट नोट्स के जरिए शेल कंपनियों में भेजे गए। इस हरियाणा मामले में अब तक सीबीआई 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 6 बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के 3 लोक सेवक, 2 कंपनियां और 6 निजी व्यक्ति शामिल हैं। सीबीआई ने चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से जुड़े दो अन्य मामलों की जांच भी अपने हाथ में ली है। इनमें एक मामला चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और चंडीगढ़ नगर निगम से संबंधित है, जबकि दूसरा मामला क्रेस्ट चंडीगढ़ से जुड़ा है। इन दोनों मामलों में भी सीबीआई की ओर से एक–एक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। सीएससीएल मामले में सीबीआई ने 5 बैंकर्स, 1 सीएससीएल अधिकारी और 1 निजी व्यक्ति को चार्जशीट किया है। क्रेस्ट चंडीगढ़ मामले में 5 बैंकर्स, 2 क्रेस्ट अधिकारी, 4 निजी व्यक्ति और 2 कंपनियों को चार्जशीट किया गया है।

ग्रामीण सेवा शिविरों का पूरा लाभ उठाएं ग्रामीण : मीणा

धौलपुर (हिंस)। जिले में आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जन–कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ सीधे उनके घर–द्वार तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 15 जुलाई तक आयोजित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अपर जिलाधिकारी हरिराम मीणा ने मंगलवार को जिले के राजाखेडा उपखंड के दिहौली में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविर में दी जा रही सुविधाओं की पड़ताल की। मीणा ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पंहुचाने के लिए प्रदेश के साथ–साथ जिले में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीणों को इन शिविरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने शिविर में मौजूद अधिकारियों से कहा कि शिविर में आने वाले लोगों को पूरा लाभ प्रदान किया जाए। इस कार्य में कोताही बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तहसीलदार एवं पटवारी को बंटवारनामा नजरी नक्शा तैयार कर किए जाने के निर्देश भी दिए। शिविर में राजाखेडा की उपखंडाधिकारी श्रीमती सुशीला मीणा एवं राजाखेड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी नवल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा 03 जमाबंदी शुद्धियां, 03 नामान्तकरण, 60 जाति सत्यापन एवं 40 पीएम किसान आवेदन का सत्यापन किया गया। आयुर्वेद विभाग द्वारा 31 मरीजों का एवं चिकित्सा विभाग द्वारा 53 लोगों का इलाज किया गया एवं 25 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 10 बच्चों को पोषण ट्रेकर से जोड़ा गया। पशुपालन विभाग द्वारा अग्रिम शिविर के दौरान 34 पशुओं का इलाज किया गया एवं 15 बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया।

पंजाब में एक हजार पदों पर होगी लेक्चरर भर्तियां, सरकार ने जारी की अधिसूचना

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब सरकार ने उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में लेक्चरर कैडर के अंतर्गत 1013 पदों पर भर्तियां करने का फैसला लिया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन भर्तियों के लिए एक जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अधिसूचना के अनुसार इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 31 जुलाई तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इस भर्ती में सबसे अधिक पद हिस्ट्री विषय के लिए निर्धारित किए गए हैं। कुल 1, 013 पदों में 829 नियमित और 184 बैकलॉग वैकेंसी शामिल हैं। भर्ती से संबंधित विषयवार पदों का विवरण, पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी भी नोटिफिकेशन में जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के तहत 12 अलग–अलग विषयों में लेक्चररों की नियुक्ति की जाएगी। सबसे अधिक 210 पद हिस्ट्री विषय के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा इंग्लिश के 141, पॉलिटिकल साइंस के 131, मैथ्स के 105, पंजाबी के 99, कॉमर्स के 98, फिजिक्स के 58, इकोनॉमिक्स के 50, केमिस्ट्री के 41, बायोलॉजी के 37, हिंदी के 29 और जियोग्राफी के 14 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदकों के लिए शैक्षणिक योग्यता के तहत संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड डिग्री अनिवार्य है।

मुहर्रम जुलूस में बंदूक लहराने का वायरल वीडियो निकला फर्जी, लकड़ी की नकली बंदूक बरामद

सुपौल (हिंस)। जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गणपतगंज हाता टोला में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक युवक द्वारा बंदूक लहराने का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जांच में फर्जी निकला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान कर उसके घर से लकड़ी की बनी एक नकली बंदूक बरामद की है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। राघोपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार राय ने बताया कि 25 जून 2026 को राघोपुर प्रखंड में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था। इसके अगले दिन 26 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें काला शर्ट और नीली जींस पहने एक युवक गणपतगंज से राघोपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर हाता टोला के समीप जुलूस के दौरान हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। पुलिस ने वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए सनहा संख्या–773/26 दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के क्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, चौकीदारों और ग्रामीणों की मदद से वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान की गई। सत्यापन के बाद 28 जून को युवक की पहचान गणपतगंज हाता टोला वार्ड संख्या–04 निवासी मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी के 21 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नजीर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो गया था। थानाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी धार्मिक जुलूस में हथियार का प्रदर्शन करना और प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करना संज्ञेय अपराध है। इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा–223 और आर्म्स एक्ट की धारा–25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। रविवार रात पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमारी की, जहां से वीडियो में दिखाई देने वाली बंदूक जैसी वस्तु बरामद की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि वह कोई वास्तविक आग्नेयास्त्र नहीं, बल्कि लकड़ी से बनी एक नकली बंदूक थी। पुलिस ने बताया कि बरामद वस्तु और वायरल वीडियो में दिख रही बंदूक एक जैसी प्रतीत होती है।

हरियाणा में लगातार कमजोर हो रही शिक्षा व्यवस्था : कुमारी सैलजा

चंडीगढ़ (हिंस)। सिरसा सांसद एवं कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हरियाणा की सरकारी शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और सरकार समय पर शिक्षक भर्ती तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है। सैलजा ने आरोप लगाया कि सरकारी शिक्षा संस्थानों को कमजोर कर निजीकरण का रास्ता तैयार किया जा रहा है, जिसका सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों पर पड़ेगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में 5, 573 वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक पद, 8, 449 प्राथमिक शिक्षक पद और 2, 413 माध्यमिक शिक्षक पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी के कारण लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शिक्षा व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रदेश के 968 सरकारी प्राथमिक विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 22.1 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात निर्धारित मानकों से भी खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की मूल भावना के अनुरूप नहीं है और सरकार को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। सैलजा ने आरोप लगाया कि शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में भी सरकार सफल नहीं रही है। उनके अनुसार 63 बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय, 112 बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालय, 132 गांवों में माध्यमिक विद्यालय और 215 गांवों में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इसे ग्रामीण विद्यार्थियों के साथ अन्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के सरकारी दावों के बावजूद 691.88 करोड़ रुपए के विकास कार्य अब भी लंबित हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में किया अहिल्याबाई होल्कर प्रतिमा का लोकार्पण
कहा, प्रेरणादायक रहा उनका राजकाज

आगरा (हिंस)। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कस्बा एत्मादपुर में मॉडल स्कूल ग्राउंड पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री भारत मंत्री और सांसद आगरा प्रो. एसपी सिंह बघेल की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर प्रतिमा अनावरण किया और मॉडल स्कूल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर लोकमाता के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई का जीवन समर्पण, त्याग और सेवा का प्रतीक है, जो आज भी शासकों को प्रेरणा देता है। नीति, सत्य, न्याय, संवेदना, आध्यात्मिक और संस्कृति की प्रेरणा के साथ लोकमाता ने देश के अलग–अलग राज्यों में चेतना का पुनर्जागरण किया व नई दिशा दी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद अध्यक्ष प्रो. राम शंकरराव शिंदे द्वारा नवी मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो फ्लाईट द्वारा करीब दोपहर दो आगरा पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे जहां करीब 1 घंटे बाद ओम बिरला भी मथुरा से कार द्वारा सर्किट हाउस पहुंच गए, सर्किट हाउस पर राज्यसभा सांसद भाजपा नंवीन जैन, विधायक फतेहपुर सीकरी चौ. बाबूलाल, पूर्व विधायक भाजपा चौ. उदयभान सिह, प्रदीप भाटी, विजय शिवहरे एमएलसी, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रशान्त पौनिया, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता मौजूद रहे। सर्किट हाउस से ओम बिरला के साथ ही प्रो. शिंदे कार में सवार होकर एत्मादपुर कार्यक्रम स्थल करीब 4 बजे पहुंचे। और लोक माता की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। मंच पर कार्यक्रम आयोजक केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद आगरा एसपी सिंह बघेल के अलावा राज्यसभा सांसद नवीन जैन, विधायक फतेहपुर सीकरी चौ. बाबूलाल, विधायक एत्मादपुर डॉ. धर्मपाल सिंह, विधायक आगरा छावनी डॉ. जीएस धर्मेश, विधायक आगरा उत्तरी पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, विधायक फतेहाबाद छोटेलाल वर्मा, विधायक खेरागढ़ भगवान सिह कुशवाह, प्रदेश अध्यक्ष महिला आयोग उप्र बबीता चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया, पूर्व विधायक उदयभान सिह, पूर्व विधायक कालीचरन सुमन, पूजा पाल, प्रदीप भाटी, आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे मौजूद है।

विद्यालय भवनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, जर्जर भवन तत्काल किए जाएं बंद : एसीएस

जयपुर (हिंस)। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा, मरम्मत और निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व में चिन्हित जर्जर विद्यालय भवनों के साथ–साथ वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे सभी विद्यालय भवनों की दोबारा गहन जांच कराई जाए। प्रत्येक भवन का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा जो भवन या कक्ष किसी भी दृष्टि से असुरक्षित पाए जाएं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर बैरिकेडिंग की जाए और उनके उपयोग पर रोक लगाई जाए। साथ ही उनकी विस्तृत रिपोर्ट विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं नवीन भवनों के निर्माण कार्य निर्धारित समय–सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने बताया कि इन कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, इसलिए किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। बैठक में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। यादव ने कहा कि विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना होगा, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंच सके।

जयपुर में हुआ नेशनल टैलेंट ऑफ इंडिया ऑडिशन

जयपुर (हिंस)। राजधानी जयपुर में मंगलवार को आयोजित नेशनल टैलेंट ऑफ इंडिया बिग ब्यूटी ऑडिशन में युवा प्रतिभाओं का उत्साह देखने को मिला। जयपुर में आयोजित ऑडिशन में 500 से अधिक युवतियों ने पंजीकरण कराया, जबकि करीब 100 प्रतिभागियों ने विभिन्न चयन चरणों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीप फोटोग्राफी रहे। आयोजन के दौरान कास्टिंग डायरेक्टर धीरज शाह ने बताया कि ऑडिशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिभाशाली युवतियों को मंच उपलब्ध कराना है, जो मेहनत और प्रतिभा के दम पर मॉडलिंग एवं ग्लैमर इंडस्ट्री में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक कारणों से उन्हें उचित अवसर नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि यह पहल नए चेहरों को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को पहचान दिलाने की दिशा में एक प्रयास है। ऑडिशन की जूरी सदस्य मिस हिमानी टेलर ने बताया कि प्रतिभागियों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया गया और उन्हें मंच पर बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है तथा इसका उद्देश्य केवल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है, न कि व्यावसायिक लाभ अर्जित करना। प्रतिभागियों के लिए चार अलग–अलग राउंड आयोजित किए गए, जिनमें आत्मविश्वास, प्रस्तुति, व्यक्तित्व और मंच संचालन क्षमता के आधार पर अंक दिए गए। इन चरणों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का चयन आगामी फिनाले के लिए किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों ने पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपनी प्रस्तुति देकर निर्णायकों को प्रभावित किया। आयोजकों ने बताया कि यह मंच प्रतिभा, मेहनत और ईमानदारी को सम्मान देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, ताकि नए चेहरे मॉडलिंग जगत में अपनी अलग पहचान बना सकें। इस आयोजन में पवन इवेंट्स, ब्लश बाय शिखा तथा फोटोग्राफी टीम के सदस्य मनोज, देवेंद्र सिंह, लेखराज और संजू ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजन के सफल संचालन में नेशनल टैलेंट ऑफ इंडिया की पूरी टीम का विशेष सहयोग रहा। जोधपुर में देश के पहले वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो का 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा जोधपुर (हिंस)। भारतीय रेलवे की आधुनिक रेल परियोजनाओं के तहत जोधपुर में विकसित किए जा रहे देश के पहले वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो के निर्माण के प्रथम चरण का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह परियोजना भविष्य में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि डिपो को वंदे भारत स्लीपर सेवाओं की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। यहां 24 कोच वाली पूर्ण ट्रेन के रखरखाव की सुविधा उपलब्ध होगी तथा एक समय में तीन ट्रेनों का निरीक्षण एवं मेंटेनेंस किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण का कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, जबकि दूसरे चरण की टेंडर प्रक्रिया जारी है और शीघ्र निर्माण कार्य शुरू किए जाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में छह सौ मीटर लंबे शेड और निरीक्षण पिट का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि पिट के बीच प्लेटफॉर्म, ड्रेनेज व अन्य कार्य प्रगति पर हैं। डीआरएम के अनुसार डिपो में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें इंस्पेक्शन पिट्स, सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग सिस्टम, ड्रॉप पिट टेबल, पिट व्हील लेथ, ऑटोमेटेड वॉशिंग सिस्टम तथा व्हील एवं बॉगी मेंटेनेंस की सुविधाएं शामिल हैं। इससे रखरखाव प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और समयबद्ध हो सकेगी। वंदे भारत स्लीपर सेवाओं के विस्तार के साथ जोधपुर का यह डिपो भारतीय रेलवे के आधुनिक मेंटेनेंस नेटवर्क में महत्वूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। करीब 30 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित इस परियोजना के दूसरे चरण में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र एवं सिमुलेटर रूम स्थापित किए जाएंगे, जहां कर्मचारियों को नई तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्कूल में मनाई गई हूल दिवस नागार्जुन की जयंती पर श्रद्धांजलि

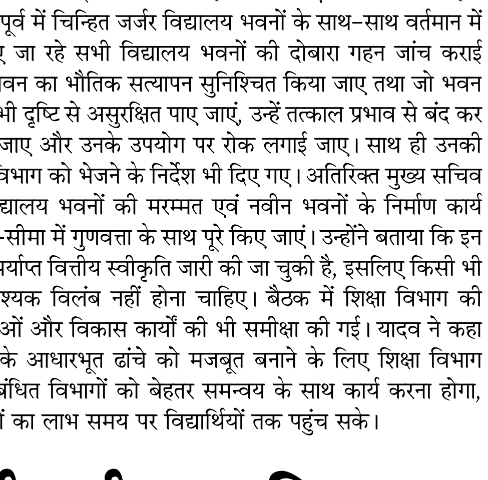

अररिया (हिंस)। फारबिसगंज के तिरसकुण्ड स्थित प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला मधुरा में हूल क्रांति दिवस मनाई गई। वहीं बाबा नागार्जुन की जयंती पर स्कूल के शिक्षक समेत बच्चों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक कुमार राजीव रंजन ने कहा कि हर वर्ष 30 जून हुल क्रांति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1855 में संथाल आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश हुकूमत, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक विद्रोह की याद में मनाया जाता है । 30 जून 1855 को झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में लगभग 50 हजार संथाल एकत्र हुए थे। क्रांति के नायक इस सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू भाई चांद और भैरव और बहनें फूलों और झानों ने किया था। उन्होंने बताया कि हूल का अर्थ क्रांति या विद्रोह होता है। इस संघर्ष में लगभग 20 हजार से अधिक आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आदिवासी समाज ने लगान देने से साफ मना कर दिया था। यह दिन आदिवासी समाज के अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान को नमन करने और उनके सांस्कृतिक गौरव को याद करने के लिए समर्पित है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कवि सह शिक्षक संजीत कुमार निगम ने कहा कि आज ही के दिन कवि नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी जिला में हुआ था। वह प्रतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि थे। नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। धन्यवाद के प्रणेता के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। नागार्जुन का असली नाम बैजनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया।

खाद्य महंगाई का खतरा, आलू, प्याज, टमाटर के दामों में फिर तेजी

गर्मी और आपूर्ति बाधित होने से बढ़े दाम, दिल्ली में टमाटर दोगुना महंगा

नई दिल्ली

देश के कई शहरों में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। इन प्रमुख सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे आने वाले समय में खाने-पीने की चीजों की महंगाई यानी कि खाद्य मुद्रास्फीति (फूड इंफ्लेशन) बढ़ने का डर सताने लगा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक महीने में टमाटर की औसत खुदरा कीमत में 18 फीसदी, प्याज में 11 फीसदी और आलू में 1.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। यदि साल-दर-साल के आधार पर देखें तो टमाटर 25 फीसदी और प्याज 3.3 फीसदी महंगा हुआ है, जबकि आलू की कीमतों में 17 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। भीषण गर्मी और आपूर्ति श्रृंखला में कमी का सीधा असर सब्जियों की कीमतों पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में टमाटर 50 फीसदी तक महंगे हो गए हैं, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। विभिन्न राज्यों में प्याज की कीमतों में भी 10-20 फीसदी का इजाफा देखा गया है। अल-नीनो प्रभाव और बारिश में देरी के कारण पड़ी भीषण गर्मी ने विशेष रूप से टमाटर जैसी नाजुक फसल को सबसे अधिक प्रभावित किया है। आजादपुर प्याज व्यापारी संघ के अनुसार, टमाटर की कम आवक के साथ-साथ गर्मी के कारण इसके परिवहन में भी परेशानी आ रही है।

चीन की अर्थव्यवस्था को एआई हार्डवेयर का सहारा, जून में विनिर्माण बढ़ा

हांगकांग। कृत्रिम मेधा (एआई) हार्डवेयर की मजबूत निर्यात मांग के दम पर जून में चीन की विनिर्माण गतिविधियों में तेजी दर्ज की गई है। मंगलवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी एक आधिकारिक सर्वेक्षण के मुताबिक, देश का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मई के 50 से बढ़कर जून में 50.3 पर पहुंच गया, जो गतिविधियों में विस्तार का संकेत है। यह आंकड़ा अर्थशास्त्रियों के अनुमान से बेहतर रहा और धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था की चिंताओं के बीच राहत लेकर आया। सर्वेक्षण से पता चला कि नए ऑर्डर का उप-सूचकांक मई के 49.9 से बढ़कर जून में 51.2, और उत्पादन का उप-सूचकांक 51.2 से बढ़कर 51.4 हो गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुख्य सांख्यिकीविद हुओ लिहुई ने कहा कि जून के आंकड़े आर्थिक गतिविधियों में सुधार का रुख दर्शाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि एआई उत्पादों के बढ़ते निर्यात से चीन इस साल के 4.5 से 5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को हासिल कर सकता है।

न्यूज ब्रीफ

सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च हुआ अथर्व पॉलीप्लास्ट का आईपीओ, 7 जुलाई को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली। प्लास्टिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी अथर्व पॉलीप्लास्ट लिमिटेड का 27 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में दो जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद तीन जुलाई को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि छह जुलाई को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर सात जुलाई को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन दोपहर 2:55 बजे तक ये आईपीओ 89 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 55 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 2,000 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 4,000 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,40,000 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 45 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 47.33 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 33.38 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.27 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.02 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए हॉरिजॉन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं आरके स्टॉक होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है।

भारतीय उद्योग में तेजी, मई में आईआईपी ग्रोथ 5.1 फीसदी पर पहुंची

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत में, मई महीने में देश की औद्योगिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा है। फैक्ट्रियों का उत्पादन मापने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) बढ़कर 5.1 फीसदी पर पहुंच गया है, जो अप्रैल के 4.9 फीसदी से अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य श्रेय मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और बिजली उत्पादन को जाता है, जो उद्योगों में निरंतर मजबूती को दर्शाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मोटर वाहन, कंप्यूटर और टेक्सटाइल जैसे उद्योगों ने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं, बिजली और गैस सप्लाई सेक्टर में 9.9 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी हुई, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन 18% बढ़ा। एंटीक ब्रोकिंग के मुताबिक, पूंजीगत वस्तुओं (कैपिटल गुड्स) का उत्पादन 12.9 फीसदी बढ़ा, जो कंपनियों के बढ़ते निवेश का स्पष्ट संकेत है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (कंज्यूमर ड्यूरेबल्स) में भी 7.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, कुछ चिंताएं भी बरकरार हैं।

बीएटी में 9,000 नौकरियों की छंटनी, सिगरेट से वेप की ओर शिफ्ट

नई दिल्ली। दुनिया की प्रमुख तंबाकू कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (बीएटी) ने वैश्विक स्तर पर लगभग 9,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। यह फैसला सिगरेट की घटती मांग और कंपनी के व्यापार मॉडल को पारंपरिक तंबाकू से हटाकर वेप, ई-सिगरेट और निकोटीन पाउच जैसे स्मोक-फ्री उत्पादों पर केंद्रित करने की रणनीति का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएटी इस साल के अंत तक 5,500 कर्मचारियों को निकालेगी, जबकि करीब 3,500 पदों को आउटसोर्स किया जाएगा। यह कदम कंपनी के अमेरिका से बाहर के 47,000 कर्मचारियों में से लगभग 20 प्रतिशत को प्रभावित करेगा। इस पुनर्गठन का लक्ष्य 2028 तक सालाना करीब 600 मिलियन पाउंड (लगभग 6,800 करोड़ रुपये) की लागत बचाना है। कंपनी का मानना है कि 2026 तक रेगुलर सिगरेट की वैश्विक बिक्री में 2 प्रतिशत की गिरावट आएगी, इसलिए व्यूस और वेलो जैसे नए उत्पादों पर बड़ा निवेश किया जा रहा है, जिनसे भविष्य की आधी से ज्यादा आय अर्जित करने का लक्ष्य है। छंटनी के साथ बीएटी कई फैक्टरियों को बंद कर रही है और प्रशासनिक कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) व ऑटोमेशन का उपयोग बढ़ा रही है। बीएटी के सीईओ टाडेउ मारोको ने इस कठिन निर्णय पर दुःख व्यक्त करते हुए प्रभावित कर्मचारियों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है।

सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च हुआ विनीत मोबाइल का आईपीओ, 7 जुलाई को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

मल्टी ब्रैंड रिटेल मोबाइल बिजनेस के काम में लगी विनीत मोबाइल लिमिटेड का 34.13 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 02 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 03 जुलाई को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 06 जुलाई को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 07 जुलाई को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन दोपहर 2:40 बजे तक ये आईपीओ सिर्फ चार प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था।

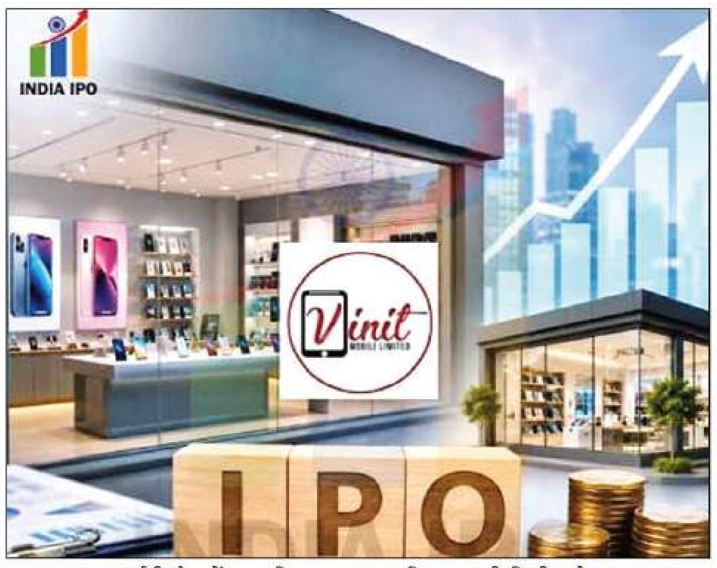

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 150 रुपये से लेकर 158 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 800 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 1,600 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,52,800 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 21.60 लाख नए शेयर बेचे जा रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए सिर्फ एक प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 56 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 38 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए पांच प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए कंफर्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं, कंफर्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड ही कंपनी का मार्केट मेकर भी है। विनीत मोबाइल की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 72 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 3.90 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीने यानी अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी को 5.11 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका था। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 28.59 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 60.63 करोड़ के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीने यानी अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी को 56.01 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका था। इस दौरान कंपनी पर लदे कर्ज के बोझ में उतार-चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 3.10 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में मामूली गिरावट के साथ 3.04 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं, पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीने में यानी अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक की बात करें, तो इस दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ उछल कर 6.07 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इस अवधि में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस भी लगातार बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 69 लाख रुपये के स्तर पर था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 4.59 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीने यानी अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक की बात करें, तो इस दौरान कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 5.70 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया था। इस अवधि में कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 70 लाख रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 4.60 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं, पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीने यानी अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक ये कंपनी का नेटवर्थ बढ़ कर 9.71 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

इसी तरह ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमॉर्टाइजेशन) 2023-24 में 1.05 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 5.72 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं, पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीने यानी अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक ये बढ़ कर 7.53 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया था।

तेजा इंजीनियरिंग का आईपीओ खुला, 7 जुलाई को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए सर्विस देने वाली कंपनी तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का 37.36 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में दो जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद तीन जुलाई को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि छह जुलाई को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर सात जुलाई को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन दोपहर तीन बजे तक ये आईपीओ सिर्फ एक प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 220 रुपये प्रति शेयर का मूल्य तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 600 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 1,200 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,64,000 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 16.98 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 47.49 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए भी 47.49 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.02 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं बीएन राठी सिक्योरिटीज लिमिटेड और एसबीसीएम सिक्योरिटीज प्रा.लि. कंपनी के मार्केट मेकर हैं। तेजा इंजीनियरिंग की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 1.27 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 2.16 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 4.02 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीने में यानी अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी को चार करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका था।

दिल्ली कैबिनेट ने नई ईवी नीति को दी मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी के प्रदूषण पर लगाम कसने और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई ईवी नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति 1 जुलाई से दिल्ली में लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी, जिसका लक्ष्य दिल्ली को एक स्वच्छ महानगर में बदलना है। इस नीति के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को 30,000 और तिपहिया वाहन खरीदने वालों को 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सभी ईवी पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसमें 30 लाख तक के चार पहिया वाहन शामिल हैं। पुरानी बीएस-आईवी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर 10,000 से 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन भी मिलेगा। सरकार ने भविष्य की गतिशीलता के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। अगले साल 1 जनवरी से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। अगले चार सालों में 15,000 करोड़ का निवेश कर 30,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य है। नीति अब उपराज्यपाल की अंतिम मंजूरी के लिए भेजी गई है, जिससे दिल्ली में ईवी को अपनाने और वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

सर्राफा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चांदी के भाव में बदलाव नहीं

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान कमजोरी नजर आ रही है। भाव में आई गिरावट के कारण चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर दूसरे सर्राफा बाजार में सोना 1,850 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,020 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। वहीं चेन्नई में सोने के भाव में 770 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 900 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की कमजोरी दर्ज की गई है। चांदी के भाव में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सोने की कीमत में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,41,920 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,45,080 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,30,090 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,32,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में भी 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,42,070 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,240 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,41,920 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,30,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,41,970 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,140 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,45,080 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,32,990 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,41,920 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,30,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,30,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,42,070 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,30,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,30,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,42,070 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,30,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में कमजोरी दर्ज की गई है।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स फिलहाल गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट पिछले सत्र के दौरान टेक्नोलॉजी शेयरों में आई तेजी के कारण मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 306.63 अंक यानी 0.59 प्रतिशत उछल कर 52,182.74 अंक के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 86.41 अंक यानी 1.18 प्रतिशत की छलांग लगा कर 7,440.43 अंक के स्तर पर पिछले स्तर के सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 522.53 अंक यानी 2.07 प्रतिशत की उछाल के साथ 25,820.14 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.04 प्रतिशत की सांकेतिक कमजोरी के साथ 52,161.65 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के कारोबार के बाद कमजोरी के साथ लाल निशान में बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 10,484.22 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.21 प्रतिशत फिसल कर 8,367.33 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 0.18 प्रतिशत टूट कर 24,626.89 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशिया में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से छह के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि तीन सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.53 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,181.29 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 285.68 अंक यानी 1.24 प्रतिशत लुढ़क कर 22,741 अंक के स्तर पर आ गया है। जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स बड़ी गिरावट का शिकार हो गया है। फिलहाल यह सूचकांक 143.83 अंक यानी 2.47 प्रतिशत टूट कर 5,676.96 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 0.21 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,004 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,583.30 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। ताइवान वेटेड इंडेक्स ने बड़ी छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 1,389.26 अंक यानी 3.09 प्रतिशत उछल कर 46,389.16 अंक के स्तर पर आ गया है।

इसी तरह कोस्पी इंडेक्स भी इंडेक्स भी जोरदार मजबूती दिखा रहा है। फिलहाल यह सूचकांक 125.35 अंक यानी 1.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,520 अंक के स्तर पर पहुंच गया है।। इसके अलावा निक्केई इंडेक्स 992.89 अंक यानी 1.43 प्रतिशत की छलांग लगा कर 70,461 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.20 प्रतिशत की मजबूती के साथ 4,082.13 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में विराट की वापसी के बाद ईशान नंबर 4 पर बल्लेबाजी करें : रायुडू

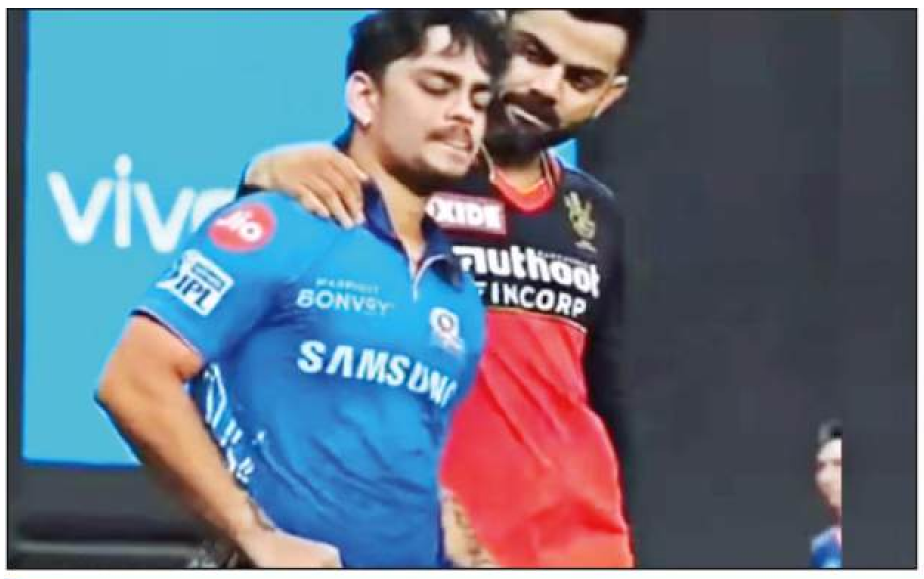

हैदराबाद

पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायुडू ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में विराट कोहली की वापसी को देखते हुए बल्लेबाज ईशान को चौथे नंबर पर उतारा जाना चाहिये। रायुडू के अनुसार ईशान बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिससे ईशान स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

रायुडू ने ईशान किशन के हाला के अच्छे प्रदर्शन की तारीफ की और कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में उनकी बल्लेबाजी काफी अच्छी थी। धर्मशाला में 34 रन और लखनऊ में 125 रन की अपनी पारियों से इस बल्लेबाज ने अपने को साबित किया है। रायुडू के विश्लेषण के मुताबिक, विराट कोहली के नंबर-3 पर लौटने के बाद, ईशान के लिए नंबर-4 सबसे उपयुक्त स्थान होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नंबर-4 पर ईशान किशन और नंबर-5 पर श्रेयस अय्यर की जोड़ी भारत के मध्यक्रम को बेहद मजबूत और स्थिर बना सकती है।

रायुडू ने विराट कोहली की मानसिक दृढ़ता और फिटनेस की जमकर तारीफ की। रायुडू ने कहा कि विराट अपनी तैयारी, फिटनेस और प्रक्रिया को लेकर बेहद अनुशासित हैं। उन्हें हमेशा पता होता है कि खराब दौर हमेशा नहीं रहेगा। उनकी यह लगन युवा खिलाड़ियों के लिए एक नया मानक स्थापित करती है। कई क्रिकेटरों ने उनसे प्रेरणा लेकर अपने करियर को बेहतर बनाया है।

वहीं रायुडू ने कहा कि 2027 एकदिवसीय विश्वकप को देखते हुए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल को लगातार अवसर दिये जाने चाहिये। उन्होंने भरोस जताया कि है कि रोहित 2027 विश्व कप की योजनाओं का एक अभिन्न हिस्सा रहेंगे। रायुडू ने कहा कि उनका अनुभव टीम के लिए अमूल्य है और वे न केवल मैदान पर, बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी टीम का माहौल सकारात्मक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जोर दिया कि बड़े मैचों में रोहित हमेशा ही असाधारण प्रदर्शन करते हैं। तकनीकी और शारीरिक रूप से वे पूरी तरह सक्षम हैं, और सही समय पर मानसिक रूप से खुद को तैयार करना उन्हें बखूबी आता है। रायुडू ने युवा यशस्वी जायसवाल को भी भारत की भविष्य की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

न्यूज़ ब्रीफ

एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित, हरमनप्रीत कौर को मिली कप्तानी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की महिला चयन समिति ने सितंबर 2026 में जापान के ऐची-नागोया में होने वाले 2026 एशियाई खेलों के लिए मंगलवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान एक बार फिर हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। भारतीय महिला टीम इस टूर्नामेंट में गत चैंपियन के रूप में उतरेगी। भारत ने 2023 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। अब टीम उस सफलता को दोहराने के इरादे से जापान जाएगी। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाओं को भी मौका दिया गया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, विकेटकीपर ऋचा घोष और जी. कमलिनी टीम का हिस्सा हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में रेणुका ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, श्री चरणी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा को शामिल किया गया है। हालांकि, ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल का चयन उनकी फिटनेस क्लियरेंस के अधीन रखा गया है। 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला टीम- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल* (फिटनेस क्लियरेंस के अधीन), राधा यादव, नंदिनी शर्मा।

फीफा विश्व कप 2026: मोरक्को ने शूटआउट में नीदरलैंड्स को हराकर अंतिम-16 में बनाई जगह

मेक्सिको। फीफा विश्व कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में मंगलवार को मोरक्को ने रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर अंतिम-16 में प्रवेश कर लिया। निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। मोरक्को के गोलकीपर यासीन बूनू ने शूटआउट में शानदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड्स के चौथे पेनल्टी शॉट को रोक दिया। इसके बाद इस्माइल साइबारी ने निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदलकर अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई। अब अंतिम-16 में मोरक्को का सामना कनाडा से होगा। गाक्पो ने दिलाई बढ़त, लेकिन दियोप ने इंजरी टाइम में किया बराबरी का गोल दूसरे हाफ के मध्य में कोडी गाक्पो ने गोल कर नीदरलैंड्स को 1-0 की बढ़त दिलाई। यह गोल उनके लिए भावनात्मक भी रहा क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी साथी ने अपने अजन्मे बच्चे के निधन की जानकारी दी थी।

ब्राजील फीफा विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, जापान को 2-1 से हराया

टेक्सास। गैब्रियल मार्टिनेली के शानदार गोल से ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 के केराउंड ऑफ 16में जगह बना ली है। पांच बार की खिताब विजेता ब्राजील इस मैच में अपने पुराने अंदाज में दिखी। मार्टिनेली के इंजरी समय के पांचवें मिनट में किये निर्णायक गोल की सहायता से उसे ये जीत मिली है। जापान ने शुरुआत से ही हमले शुरु कर दिये। मैच के 29वें मिनट में डैनिलो से मिले पास पर काइशू सानो ने एक शानदार मैदानी गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद दूसरे हाफ में वापसी करते हुए ब्राजील की टीम हावी रही और उसने जापानी रक्षापंक्ति पर दबाव बनाये रखा। दिग्गज मिडफील्डर कैसिमिरो ने 56वें मिनट में गैब्रियल मैगलहेस के क्रॉस पर हैडर से एक शानदार गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद विनीसियस जूनियर ने एक बेहतरीन मूव बनाया पर जापानी गोलकीपर जायन सुजुकी ने इसे विफल कर दिया।

फुटबाल पर भारी निवेश के बाद भी विश्वकप में प्रभावित नहीं कर पायीं कतर और सऊदी अरब

मियामी

फीफा विश्व में सऊदी अरब और कतर की टीम का प्रदर्शन बेहद रखा रहा और ये दोनो ही किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ पायीं जबकि इन देशों ने फुटबाल के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मोटी रकम खर्च की थी। वहीं आर्थिक बदहाली से जूझ रही अफ्रीकी टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इससे ये साबित हो गया है कि है कि खेल में मोटी रकम का निवेश करना सफलता की गारंटी नहीं बन सकता। धनी देशों सऊदी अरब और कतर ने पिछले कुछ साल में फुटबाल के बुनियादी ढांचे पर काफी निवेश किया था। उसके क्लबों ने पिछले कुछ वर्षों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जैसे स्टार खिलाड़ियों को अपने क्लबों से जोड़ा पर इसके बाद भी इनकी टीमों को विश्व कप में शर्मनाक हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। इसके विपरीत, बेहद सीमित संसाधनों वाले अफ्रीकी देशों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का हैरान कर दिया है। सऊदी अरब ने अपनी फुटबाल में बदलाव लाने और उसे शीर्ष स्तर पर ले जाने के साथ ही साल 2034 में होने वाले विश्व कप की मेजबानी भी हासिल की पर विश्वकप में उसकी टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। टीम ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाई और उस ग्रुप में सबसे निचले स्थान पर रही जिसमें केप वर्दे जैसी छोटे से देश की टीम भी थी। केप वर्दे ने उसे गोलरहित ड्रा पर रोक कर विश्कप से बाहर कर दिया। इससे सऊदी अरब की 1994 के बाद पहली बार ग्रुप चरण से आगे बढ़ने की उम्मीदें टूट गयीं। उसने तीन मैच में दो ड्रा खेले और अपने ग्रुप में चौथे स्थान पर रहकर बाहर हो गया। सऊदी अरब के कोच जार्जोस डोनिस ने कहा, यह प्रदर्शन हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं था क्योंकि जब हम अपने लगभग समान स्तर की टीम के खिलाफ मैच में खेलते हैं, तो हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। इसलिए यह चिंता का विषय है। वहीं चार साल पहले विश्व कप की मेजबानी करने वाला कतर भी महज तीन मैचों के बाद बाहर हो गया। कतर ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच के अंत में बराबरी का गोल दागकर विश्व कप में पहली बार अंक हासिल किया, लेकिन उसे अपने बाकी दो मैच में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, कतर के कोच जुलेन लोपेटेगुई ने कहा, मुझे लगता है कि इससे पता चलता है कि कम से कम हम इस तरह के मैचों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। हम फुटबाल में अपने भविष्य को लेकर निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। इसके अलावा खाड़ी के अन्य देशों का प्रदर्शन भी खराब रहा। दूसरी ओर अफ्रीकी महाद्वीप की 10 में से नौ टीम नाकआउट राउंड में पहुंचीं, अफ्रीकी देशों के पास खाड़ी देशों की तरह फुटबाल पर भारी भरकम खर्च करने के लिए साधन नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा, जुनून और टीम भावना से असाधारण प्रदर्शन किया है। यह विश्व कप खाड़ी देशों के लिए एक कड़ा सबक है कि खेल के सबसे बड़े मंच पर सफलता केवल धनी के निवेश से नहीं खरीदी जा सकती। केप वर्दे और कांगो जैसे सीमित संसाधनों वाले देशों ने अपने प्रदर्शन से दिखाया है कि पैसा नहीं प्रतिभा सबसे जरुरी है।

फीफा विश्व कप 2026 : पैराग्वे ने किया बड़ा उलटफेर, जर्मनी को हराकर अंतिम-16 में किया प्रवेश

फॉक्सबोरो (बोस्टन)

चार बार की विश्व चैंपियन जर्मनी का फीफा विश्व कप 2026 का सफर सोमवार को सनसनीखेज अंदाज में समाप्त हो गया। पैराग्वे ने 120 मिनट तक मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को 4-3 से हराकर टूर्नामेंट के अंतिम-16 में जगह बना ली। निर्णायक पेनल्टी जोसे कैनाले ने गोल में बदलकर पैराग्वे को ऐतिहासिक जीत दिलाई।

यह विश्व कप इतिहास में पैराग्वे की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। 2010 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीम ने लंबे अंतराल के बाद विश्व कप में वापसी करते हुए अब प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अब उसका सामना फ्रांस और स्वीडन के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा। जर्मनी ने मैच की शुरुआत से ही गेंद पर कब्जा बनाए रखा। कोच जूलियन नागेल्समैन ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए इस विश्व कप में तीन गोल और दो असिस्ट करने वाले डेनिज़ उंडाव को पहली बार शुरुआती एकादश में शामिल किया। जर्मनी ने पहले हाफ में लगातार दबाव बनाया, लेकिन कोई भी शॉट लक्ष्य पर नहीं लगा सका। इसका फायदा पैराग्वे ने 35वें मिनट के बाद उठाया। मिगुएल अल्मीरोन की वापसी के साथ टीम ने शानदार जवाबी हमला किया और जूलियो एनसिसो ने दमदार हेडर के जरिए गोल कर पैराग्वे को 1-0 की बढ़त दिला दी। यह विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे का पहला गोल भी था। दूसरे हाफ में जर्मनी ने वापसी की। 54वें मिनट में फ्लोरियन विर्ट्ज़ के सटीक क्रॉस पर काई हैवर्ट्ज़ ने हेडर लगाकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों को कई मौके मिले, लेकिन कोई भी निर्णायक बढ़त नहीं बना सका। अतिरिक्त समय में जर्मनी ने 102वें मिनट में जोनाथन ताह के हेडर से गोल किया, लेकिन लंबी समीक्षा के बाद गोलकीपर पर फाउल मानते हुए इसे रद्द कर दिया गया। मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। जर्मनी की ओर से काई हैवर्ट्ज़, निक वोल्टेमाडे और जोनाथन ताह अपने प्रयास में असफल रहे।

विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट

लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में खेलती हुई बेलारुस की आर्याका सबालेंका।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में वैभव को मिल सकती है जगह

सैमसन या ईशान को दिया जा सकता है आराम

लंदन

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम बुधवार को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 क्रिकेट मैच में उतरेगी। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में मिली अप्रत्याशित हार को देखते हुए इस मैच में भारतीय टीम बदलावों के साथ उतर सकती है। इसके तहत शीर्ष क्रम में 15 साल के उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को शामिल कर सकती है।

आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में वैभव को कोई अवसर नहीं मिला। वहीं आयरलैंड के खिलाफ हार के बाद वैभव को अंतिम ग्यारह में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ शीर्ष क्रम के अन्य बल्लेबाज विफल रहे थे। ऐसे में वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का अवसर मिल सकता है। ऐस में उम्मीद है कि यह वैभव भारतीय पारी की शुरुआत करेगा। वहीं कहा जा रहा है कि बल्लेबाज संजू सैमसन को पहले मैच में आराम दिया जा सकता है। सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ दोनों टी20 मैचों में बतौर ओपनर शुरुआत की पर वह रन नहीं बना पाये थे।

पहले मुकाबले में वह केवल 5 रन जबकि दूसरे में शून्य पर ही आउट हो गये थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजू सैमसन विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर अंतिम ग्यारह में अपनी जगह बनाये रख पाते हैं या नहीं। आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सैमसन के पास थी, जबकि दूसरे मैच में ईशान किशन ने विकेटकीपिंग की थी।

ईशान भी हालांकि रन नहीं बना पाये थे। वह पहले मैच में 1 रन बनाया और दूसरे में 12 रन ही बना पाए। टीम प्रबंधन शीर्ष-3 में तीन बाएं हाथ के बल्लेबाजों वैभव और अभिषेक के साथ ईशान को शायद ही उतारे। ऐसे में सैमसन की जगह ईशान किशन को भी आराम दिया जा सकता है। दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में सिर्फ 20 गेंदों पर 49 रन की आक्रामक पारी खेली थी, जिससे इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के लिए उनकी जगह लगभग पक्की मानी जा रही है।

वहीं तेज गेंदबाजी विभाग में बड़े बदलाव की संभावना कम है इसमें सबकी नजरें सूर्यांश शेडगे पर होंगी। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर का प्रदर्शन कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था। ऐसे में शेडगे की जगह पर वॉशिंगटन सुंदर की अंतिम ग्यारह में अवसर मिल सकता है।

पहले टी20 के लिए भारत की संभावित अंतिम ग्यारह इस प्रकार हो सकती है: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

दिल्ली कैपिटल्स में वापसी से ऋषभ अपना स्वाभाविक प्रदर्शन कर पायेंगे : डिविलियर्स

बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान दे सकेंगे

जोहांसबर्ग

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ए बी डिविलियर्स का मानना है कि आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जिस प्रकार से एक बार फिर अपनी पुरानी आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की है। वह एक रणनीतिक कदम है। इससे उनके ऊपर अधिक वेतन को लेकर पड़ रहा दबाव कम होगा और वह अपना स्वाभाविक खेल दिखा सकेंगे। ऋषभ ने हाल ही में लखनऊ सुपरजयंस में मिल रहे रिकार्ड 27 करोड़ के वेतन को छोड़कर 15 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की है। डिविलियर्स का मानना है कि वेतन का कम दबाव पंत को अपना स्वाभाविक खेल दिखाने में सहायता कर सकता है। पिछले सत्र में लखनऊ के साथ मतभेदों के कारण संभव नहीं हो पा रहा था।

डिविलियर्स के अनुसार पिछले सत्र के दौरान ही ऋषभ की नाराजगी भी सुपरजायंट्स टीम से दिख रही थी। इससे भी उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ था। ऋषभ दो सत्र तक लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल रहे। वहीं इस बार ट्रेड करार के तहता वह दिल्ली कैपिटल्स में लौट आए हैं। ऋषभ ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2016 में दिल्ली कैपिटल्स से ही की थी। अब अगले आईपीएल सत्र में सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि ऋषभ अपनी पुरानी टीम में वापसी के बाद किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और दिल्ली कैपिटल्स नए बदलावों के साथ कितनी सफलता हासिल कर पाती हैं या नहीं।

लखनऊ सुपर जायंट्स में रहते हुए ऋषभ को आईपीएल में सबसे ज्यादा 27 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स में वापसी के बाद उनका वेतन घटकर 15 करोड़ रुपये रह गया है। डिविलियर्स के अनुसार पिछले सत्र में ऋषभ ने कई बार संकेत दिये थे कि वह वह टीम के माहौल से खुश नहीं हैं। टीम प्रबंधन और कोचिंग स्टाफ के साथ भी उनका तालमेल नहीं था। कप्तान के तौर पर वह लखनऊ सुपर जायंट्स में असफल रहे थे। ऋषभ के दिल्ली से जुड़ने के अलावा भी टीम में कई अन्य बदलाव इसके तहत पूर्व कप्तान सौरव गांगुली एक बार फिर टीम के क्रिकेट निदेशक की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, जबकि पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह के बल्लेबाजी कोच बनने की संभावनाए हैं।

डिविलियर्स हालांकि लगातार बदलावों को सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ज किसी टीम में बार-बार मालिक, कोच और प्रबंधन बदलते हैं तो खिलाड़ियों के लिए स्थिर माहौल बनाना मुश्किल हो जाता है। उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना आसान नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऋषभ के लिए कम वेतन पर खेलना शायद मानसिक रूप से राहत देने वाला साबित हो सकता है। इससे उन पर अपेक्षाकृत कम दबाव रहेगा और वह अपने स्वाभाविक खेल पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। हालांकि डिविलियर्स ने यह भी माना कि दिल्ली कैपिटल्स को लगातार सफल टीम बनाने के लिए प्रबंधन में स्थिरता और स्पष्ट रणनीति की जरूरत होगी।

सलाह

पार्टनर से कर रहे हैं चैट तो रखें खास बातों का ख्याल

आजकल के मॉडर्न जमाने में मोबाइल हर किसी की जरूरत बन गया है। सुबह हो या रात इसको देखे बिना आजकल के युवाओं का मन ही नहीं लगता। यहां तक की पार्टनर भी आपस में बात करने के लिए ज्यादातर चैटिंग का ही सहारा लेते हैं। कई बार तो चैटिंग से बात स्पष्ट न होने के कारण छोटी सी बात भी बड़े झगड़े का कारण बन जाती है। आप भी पार्टनर के साथ बात करने के लिए चैटिंग का सहारा ले रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें।

1. टाइम का रखें ख्याल

यह जरूरी नहीं की आपका पार्टनर हर समय चैटिंग करने के लिए फ्री हो। बिजनेस के कारण या किसी जरूरी मीटिंग के वक्त उनको डिसटर्ब न करें। बात करने के लिए सही मौके का इंतजार करें।

2. विषय से न भटके

इस बात का ख्याल रखें कि चैटिंग एक-दूसरे का हाल पूछने या फिर जरूरी बात के लिए अच्छा विकल्प है। बात करते समय विषय से न भटके

3. न करें छोटी-छोटी बात

छोटी-छोटी बात के लिए चैटिंग करने से आपके पार्टनर को बुरा भी लग सकता है। जो बात जरूरी है सिर्फ वहीं करें।

4. सहजता से करें चैटिंग

चैटिंग करते समय इस बात का ख्याल रखें कि हड़बडाहट या घबराहट में बात न करें। इससे आपको अपनी बात दूसरे को समझाने में परेशानी हो सकती है।

ज्यादा अपेक्षाएं मत पालो, आरामदायक जीवन का मंत्र

एक बार भ्रमण पर निकले दार्शनिक सुकरात की मुलाकात किसी शहर में एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग सुकरात को अपने घर ले गए। उनका भरा-पूरा परिवार था। घर में बेटे-बहुओं के अलावा पौत्र-पौत्रियां भी थे। सुकरात ने पूछा-आपके घर में तो सुख-समृद्धि का वास लग रहा है। वैसे अब आप करते क्या है? बुजुर्ग ने कहा-अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की कृपा से हमारा अच्छा कारोबार है, सारी जिम्मेदारियां अब मैंने अपने बेटों को सौंप दी हैं। घर का जिम्मा बहुएं संभालती हैं। इसी तरह जीवन चल रहा है। सुकरात ने फिर पूछा-पर आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा। बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है? सुकरात की बात सुनकर बुजुर्ग बोला-मैंने जीवन के इस मोड़ पर बस एक ही फलसफा अपनाया है कि दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं मत पालो। जो मिले, उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे-बहुओं को सौंपकर निश्चिंत हैं। अब वे जो कहते हैं, वह मैं कर देता हूं और जो कुछ भी खिलाते हैं, वह खा लेता हूं। अपने पौत्र-पौत्रियों के साथ हंसता-खेलता हूं। बच्चे जब कुछ भूल करते हैं, तब भी मैं चुप ही रहता हूं। जब कभी वे मेरे पास सलाह-मशविरे के लिए आते हैं, तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों के प्रति उन्हें सचेत कर देता हूं। मेरी सलाह पर वे कितना अमल करते हैं, यह देखना मेरा काम नहीं है। यदि वे मेरे पास पुन: आते हैं, तो मैं नेक सलाह देकर उन्हें विदा कर देता हूं। यह सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा-इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए, यह आपने बखूबी समझ लिया है।

क्या आप जानते हैं इन हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में

कभी हेयर स्टाइल का मतलब हुआ करता था बॉलीवुड के स्टार्स की तरह की स्टाइल। किसी खास फिल्म में अपने पसंदीदा कलाकार की हेयर स्टाइल की कॉपी करने तक ही हेयर स्टाइलिंग का मामला सिमटा हुआ था। इससे ज्यादा हेयर स्टाइल का कोई मतलब भी नहीं था। बीते कुछ सालों में बालों ने स्टाइलिंग के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है। इसके साथ ही शुरू हुई है हेयर स्टाइलिंग और केयरिंग प्रॉडक्ट्स की मांग।

ये हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी बाजार में बड़ी रेंज उपलब्ध होते हैं। जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रॉडक्ट्स के बारे में।

वैक्स

इसे मोल्डिंग क्रीम, स्टाइलिंग पेस्ट, क्ले या पुट्टी के तौर पर भी जाना जाता है। यह हेयर स्टाइलिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला बहुत आम प्रोडक्ट है। इसका हर दिन उपयोग किया जा सकता है। आपके बाल चाहे स्ट्रेट हों या वेवी, ज्यादा लंबे हों या फिर छोटे... हर तरह के बालों में आप वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको बालों को होल्ड करके रखता है और साथ ही हल्की-सी चमक भी देता है।

पॉमेड

यदि आप बालों को और भी ज्यादा व्यवस्थित व चमकदार चाहते हैं, तो पॉमेड सबसे उपयुक्त उत्पाद है। अपने बालों को वेल-ग्रूम्ड और एकदम संवरे हुए रखने के लिए टॉवेल से बालों को सुखाकर पॉमेड का इस्तेमाल करें। एक बार सूखने पर आपके बाल संवरे और चमकदार नजर आएंगे। चूंकि यह आपको बालों को हल्का-सा चिपचिपा बनाता है, इसलिए उन लोगों के लिए यह बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, जो अपने बालों को अपने हाथों से संवारते हैं।

क्रीम

हेयर क्रीम बालों को पूरी तरह से संवरा हुआ नहीं रखता है, लेकिन इससे लंबे और कर्ली बाल बहुत अच्छे तरीके से संभाले जा सकते हैं। हेयर क्रीम बालों को अच्छे-से नम रखता है ताकि वे सही दिशा में संवरे रहें।

ड्राय शैंपू

हर दिन बालों में शैंपू करना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे बालों से प्राकृतिक नमी कम होने लगती है और यह बालों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। यदि आप शैंपू नहीं करते हैं, तब भी आपके बाल चिपचिपे हो जाते हैं। इससे निबटने और बालों को नुकसान से बचाने के लिए आप ड्राय शैंपू का उपयोग करें। इसे आप सूखे बालों पर स्प्रे करें ताकि यह आपके बालों में से चिपचिपापन सोख ले। इससे आपके बाल एकदम फ्रेश नजर आने लगेंगे। साफ बाल ज्यादा घने भी नजर आते हैं।

जेल

जेल सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय उत्पाद है। एक अच्छा हेयर जेल हर दिन प्रयोग करने के लिए अच्छा विकल्प है। इससे आपकी स्टाइलिंग एकदम परफेक्ट रहेगी। जरा-सा जेल टॉवेल से सुखाए गए बालों पर लगाएं।

स्मार्टफोन डाटा और पैसे बचाने के लिए उपयोग करें ये 5 तरीके

प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के साथ बैलेंस को लेकर कई समस्याएं आती हैं। जैसे यूजर्स को डाटा बैलेंस खत्म होने का पता नहीं चलता है जिसके चलते मेन बैलेंस से डाटा इस्तेमाल हो रहता है। ऐसे में यूजर का सारा बैलेंस खत्म हो जाता है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। इसी परेशानी को देखते हुए हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाएं हैं जो आपका डाटा बचाने में मदद करेंगे। इससे आपका बैलेंस भी जीरो नहीं होगा।

ऐसे बचाएं मोबाइल डाटा व पैसा

» देखा जाए तो एप्स अपडेट होने में ज्यादा डाटा खर्च होता है। जैसे ही फोन में इंटरनेट कनेक्ट होता है वैसे ही एप्स अपडेट होने लगती है। ऐसे में अगर आप एप्स का ऑटो अपडेट ऑप्शन बंद कर दें या उसे ओनली वाई-फाई पर सेट कर दें तो आपका डाटा बच सकता है।

» व्हाट्सएप इस्तेमाल करते समय यह ऐप काफी डाटा खर्च करती है। दरअसल, व्हाट्सएप पर आने वाली इमेज और मीडिया फाइल्स अपने आप ही डाउनलोड हो जाती हैं। इससे यूजर्स का मोबाइल डाटा काफी खर्च होता है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाकर यूसेज पर क्लिक करना होगा। इशके बाद यहां आपको मीडिया ऑटो डाउनलोड के ऑप्शन मिलेंगे जिन्हें आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। आप इन्हें ऑटो डाउनलोड ओवर वाई-फाई पर सेट कर सकते हैं।

» अगर आप अपने स्मार्टफोन पर क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो यह इससे आपका मोबाइल डाटा ज्यादा खर्च होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोम किसी भी वेबसाइट के वेब वर्जन डाउनलोड करता है। ऐसे में आप किसी भी साइट का लाइट वर्जन ब्राउज करें। इसके लिए क्रोम सेटिंग्स पर जाकर डाटा सेवर ऑप्शन को ऑन कर दें।

» फेसबुक चलाते समय उसके वीडियोज भी ऑटो प्ले होते हं। इससे फोन का डाटा ज्यादा खर्च होता है। इसके लिए फेसबुक एप की सेटिंग में जाकर ऑटोप्ले को ऑफ कर दें।

» आपके फोन में गूगल ड्राइव, कैंडी क्रश, जीमेल जैसे कई एप्स मौजूद होंगे। ये सभी एप्स मोबइल डाटा ऑन होते ही फाइल्स को ऑनलाइन सेव/सिंक करते हैं। इससे डाटा काफी खर्च होता है। इसक लिए आप नोटिफिकेशन टॉगल में जाकर sync ऑफ कर दें।

कुछ इस तरह सुंदर पौधे लाएंगे घर में खुशहाली

फेंगशुई के अनुसार स्वस्थ और सुंदर पौधे आपके घर में खुशियां लाते हैं और घर के हर कोने को उत्साह और उमंग से सराबोर कर देते हैं।

फेंगशुई में पौधों को नौ आधारभूत सुरक्षा सावधानियों में से एक माना गया है, इसलिए घर के खाली हिस्सों में पौधे लगा देना चाहिए।

» चढ़ने वाली बेलें जिन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है जैसे- मनी प्लांट को कोने में लगाकर उस जगह की उदासीनता को कम किया जा सकता है।

» घर के दक्षिण-पूर्व कोने को धन और समृद्धि का कोना माना जाता है इसलिए यहां चौड़े पत्तियों वाले पौधे लगाना चाहिए।

» मुरझाए हुए या सूख गए पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है।

» घर के सामने वाले हिस्से में कांटेदार या नुकीले पत्तों वाले पौधे नहीं लगाना चाहिए। वे नकारात्मक ऊर्जा को सहयोग करते हैं।

» ये पौधे न सिर्फ आपके घर को बल्कि आपके जीवन को भी महकाते हैं और सबसे बड़ी बात कि इन्हें फॉलो करना बहुत कठिन भी नहीं है।

सलाह

करी पत्ते से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानते हैं आप?

करी पत्ते को मीठी नीम भी कहा जाता है। अक्सर खाने का जायका बढ़ाने के लिए घरों में करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। हमें दक्षिण भारत के व्यंजनों में ज्यादातर करी पत्ते का इस्तेमाल देखने को मिलता है। करी पत्ता ना केवल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाता है बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। करी पत्ते में मौजूद पोषक तत्व शरीर को कई बीमारियों से दूर रखते हैं। करी पत्ते में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। करी पत्ते में विटामिन ए-सी-बी-ई, आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की भरपूर मात्रा होती है। करी पत्ता बालों और त्वचा दोनों के लिए अच्छा माना जाता है।

करी पत्ते के ये फायदे जानकर हैरान हो जाएंगे आप

वजन घटाने में मददगार: अगर बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो अपने मेन्यू में करी पत्ते को शामिल करें। रोजाना करी पत्ते के सेवन से शरीर की जमी हुई चर्बी घटेगी और वजन आसानी से कम होगा।

लीवर दुरुस्त रखे : करी पत्ते में मौजूद विटामिन-ए और सी लीवर को तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। अधिक मात्रा में स्मोकिंग करने या शराब पीने से लीवर कमजोर हो जाता है। ऐसे में करी पत्ता खाना फायदेमंद साबित हो सकता है।

दिल को रखे स्वस्थ : करी पत्ते के सेवन से आप दिल से जुड़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बता दें, करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट गुण शामिल होते हैं जो शरीर में खराब कोलेस्ट्राल को बढ़ने से रोकते हैं।

एनीमिया से बचाए : करी पत्ता आयरन और फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत है, जो एनीमिया के खतरे को कम करने में सहायक है।

डायबिटीज के लिए असरदार : करी पत्ते में एंटी डायबिटिक एजेंट होते हैं। इसके लगातार सेवन से शुगर लेवल को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। करी पत्ता इन्सुलिन को प्रभावित कर ब्लड-शुगर लेवल को कम करता है।

त्वचा, बालों के लिए फायदेमंद : करी पत्ता त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। दाग-धब्बों और मुंहासों से निजात पाने के लिए करी पत्ते का इस्तेमाल करें। करी पत्ते का फेस पैक लगाने से आप चेहरे की रंगत निखार सकते हैं।

अगर काले, लंबे और घने बालों का शौक रखती हैं तो करी पत्ते का इस्तेमाल करें। करी पत्ता बालों का झड़ना, रुसी और रुखापन कम करता है। करी पत्ते को उबालने के बाद हरे रंग के पानी से बालों की अच्छे से मालिश करें।

आंखों की रोशनी बरकरार रखे : करी पत्ते में भरपूर मात्रा में विटामिन-ए होता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद होता है। करी पत्ते के लगातार सेवन से आंखों से जुड़ी बीमारियों से निजात मिल सकती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है।

इंफेक्शन से बचाए : करी पत्ते में मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण त्वचा के लिए गुणकारी हैं। त्वचा में इंफेक्शन होने पर करी पत्ते का इस्तेमाल असरदार साबित होता है।

पाचन क्रिया स्वस्थ रखे : करी पत्ता पाचन संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिलाने का बेहतरीन उपाय है। करी पत्ता कब्ज, अपच, बवासीर और डायरिया जैसी परेशानियों से आपको बचाता है।

बुलंदियों तक पहुँचायेगी अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी

समय के साथ क्वालिटी लीडरशिप की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप बिजनेस, टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी फील्ड के लिए काम कर रहे हो, खुद में लीडरशिप स्किल को लाने की कोशिश करे। क्या पता आपकी यह खासियत आपको बुलंदी पर पहुंच दे। कुछ टिप्स को अपनाकर आप अच्छी लीडरशिप डेवलप कर सकते है।

लोगों को करे प्रभवित : अपनी बुद्धिमत्ता और तार्किकता के बल पर कंपनी को फायदा पहुंचना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। आप अपने कार्य और व्यवहार से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करे। एक्सपर्ट मानते है की लीडरशिप एक आर्ट है और इसे भी निखारा जा सकता है। सभी लोग जन्मजात स्टार नहीं होते, लेकिन लीडरशिप टूल्स का उपयोग कर अपने टैलेंट को निखारते रहते है और लोगो के लिए रोल मॉडल बन जाते है।

सीखने के लिए तैयार रहे: एक अच्छा लीडर हमेशा सीखने को तैयार रहता है। यहीं कारण है कि वह हमेशा खुद को अप टू डेट रखता है। एक स्मार्ट लीडर वर्तमान से संतुष्ट रहते हुए भी नई चीजों के लिए तैयार रहता है। वह अपनी टीम को भी यही सीख देता है।

टीम का हौसला बढ़ायें : एक अच्छा टीम लीडर हमेशा अपनी टीम का सपोर्ट करता है और टीम मेंबर्स का हौसला बढ़ाता है। विपरीत परिस्थिति में टीम से खुलकर बात करता है और खुलकर बात करने का मौका भी देता है। एक्सपर्ट की माने तो लीडरशिप का सही मतलब असर डालना, दिशा दिखाना और हमेशा सपोर्ट करना है, न कि चीजों को कंट्रोल करना।

पारदर्शिता रखें : अच्छे लीडर को कार्य एवं व्यहार में पारदर्शिता दिखने कि जरूरत होती है। अपने काम के प्रति लीडर को हमेशा ईमानदारी और लगन दिखाने की जरूरत होती है। इससे वह टीम का भरोसा एवं दुसरो के लिए मानक भी स्थापित कर पता है।

जूनियर्स को सम्मान दे: जब कंपनी आपको लीडरशिप का मौका देती है, तो वह चाहती की आप उसके लिए हर तरीके से बेहतर साबित हो। इसलिए अपने जूनियर्स को सम्मान दे और आप खुद अहंकार को न बढ़ने दे।

सहयोग के लिए तैयार रहे : वर्क पैलेस पर आपकी जिम्मेदारी और जबाबदेही बनती है की आप सहयोग की भावना से काम करें। इसके साथ ही आपको स्ट्रांग लीडरशिप की कला से खुद को सजाना ही होगा।

व्यवसाय को इस प्रकार बनाये लाभकारी

कारोबार बढ़ाने में भी वास्तु के उपाय बेहद लाभदायक होते हैं। कार्यालय वह जगह है जहां लोग पेशेवर ढंग से अपने पेशे और व्यापार के लिए लक्षित होकर काम करते हैं। यह जगह धन सृजन के साथ-साथ प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की जगह है। सैद्धांतिक तौर पर ऑफिस को सकारात्मक उर्जा से भरा होना चाहिए, माहौल में रौशनी की अधिकता होनी चाहिए, साथ इसका डिजायन भी आकर्षक और सुविधाजनक होना चाहिए। भारतीय वास्तुशास्त्रों में ऑफिस को व्यवसाय स्थल, कार्यस्थान या कार्यालय कहा गया है और अनेक विस्तृत उपायों की चर्चा की गई, जिसे अपना कर लाभ उठाया जा सकता ह।

भारतीय वास्तुशास्त्रों के अनुसार कार्यालय की बिल्डिंग के लिए उसका प्लॉट चौकोर या आयताकार होना सबसे लाभकारी होता है। अनियमित आकार के भूखंडों से बचने का सुझाव इन ग्रंथों में दिया गया है। कार्यालय के बॉस या कंपनी के मालिक के बैठने का स्थान ऐसा होना चाहिए, जहां किसी आगंतुक की दृष्टि सीधे उसपे न पड़े। इसके लिए ग्रंथों में दक्षिण-पश्चिम कोने में केबिन बनाने का सुझाव दिया गया है और उनका मुख उत्तर दिशा की ओर सर्वोत्तम माना गया है। कार्यालय के सीनियर स्टाफ के लिए दक्षिण और पश्चिम में बैठना काफी वास्तुसम्मत माना गया है। साथ ही यह भी सुझाव है कि जब वे दक्षिण में बैठे हों, उनका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और पश्चिम में बैठते समय पूर्व का सामना करना चाहिए, जबकि ऑफिस के जूनियर स्टाफ के लिए पूर्व और उत्तरी भाग की जगह सर्वोत्तम मानी गई है।

रेसिपी

चटपटे राम लड्डू

सामग्री

200 ग्राम अंकुरित मूंग दाल, 60 ग्राम अंकुरित चना दाल, पानी, 2 टीस्पून भूना हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया, 1/8 टीस्पून हींग,1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून नमक, हरी चटनी स्वादअनुसार, इमली की चटनी, मूली, धनिया, चाट मसाला

विधि

मूंग दाल और चने की दाल को 3-4 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रखें। ब्लेंडर में दोनों दालों को डालकर पीसकर पेस्ट तैयार कर लें और फिर इसे एक बाउल में निकाल लें। अब इसमें जीरा, अदरक का पेस्ट, धनिया, हींग, लाल मिर्च, बेकिंग सोडा और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। एक पैन में तेल गर्म करें। अब इसे पकौड़ों की तरह फ्राई कर लें। इन्हें तबतक फ्राई करें जब तक इसका रंग गोल्डन न हो जाएं। अब तैयार किए लड्डू पर हरी चटनी, इमली की चटनी, मूली और धनिए के साथ गार्निश करें। फिर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें।

कॉर्न चीज़ बॉल्स

साम्रगी

170 ग्राम उबले हुए आलू, 220 ग्राम स्वीट कॉर्न, 70 ग्राम मोत्ज़ारेला पनीर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 1/2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, 3/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवायन की पत्ती, 1/2 टीस्पून नमक, मैदा, पानी, ब्रेडम्ब्स

विधि

एक बाउल में उबले हुए आलू और स्वीट कॉर्न डालकर अच्छे से मैश करें। अब इसमें मोत्ज़ारेला पनीर, मैदा,कॉर्न फ्लोर, लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, अजवायन की पती और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा-सा मिक्सर लेकर छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर साइड पर रख दें। एक अन्य बाउल में मैदा और पानी डालकर घोल तैयार कर लें। तैयार की बाउल में को मैदे के मिक्सर में डिप करके ब्रेडक्रम्ब्स में रोल करें। एक कड़ाही में तेल गर्म करके बाउल्स को फ्राई कर ले। कॉर्न चीज़ बॉल्स तैयार है। इन्हें गर्मा-गर्म सर्व करें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय) e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, (सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)